बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 98

दुर्लभ खनिजों के लिए हो रणनीति

अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध में कई अन्य देशों के साथ भारत भी पिस रहा है। अप्रैल में चीन ने कुछ भारी एवं मध्यम दुर्लभ खनिजों एवं इनसे जुड़े मैग्नेट के निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी और कहा था कि इनके निर्यात के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की तरफ से शुल्क एवं विभिन्न व्यापार प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद चीन ने यह कदम उठाया था। इन तत्त्वों के निर्यात के लिए लाइसेंस लेने में कठिनाई पेश आ रही है और यह साबित करना भी कम पेचीदा नहीं है कि किन उद्देश्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह से भारत में भी विनिर्माण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। चीन का आधिकारिक रूप से ज्ञात भंडार के 50 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण है और निष्कर्षण और प्रसंस्करण क्षमता में इसकी क्रमशः 70 फीसदी और 90 फीसदी हिस्सेदारी है। ये खनिज वाहन, सोलर पैनल आदि के विनिर्माण में काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। अब चीन से इन दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति बाधित होने से भारतीय उद्योगों को दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। यह निश्चित था कि चीन कभी न कभी इन तत्त्वों की आपूर्ति रोक कर इनका इस्तेमाल व्यापार में हथियार के रूप में करेगा। वास्तव में चीन अपने इस हथियार का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। जब एक दशक से अधिक समय पूर्व चीन और जापान में तनाव चल रहा था तो उस समय चीन ने जापान और उसकी कंपनियों को इन तत्त्वों की आपूर्ति रोक दी थी।

चीन के साथ अपने इस अनुभव से सबक लेते हुए जापान ने अस्थायी बाधाओं का सामना करने के लिए खनिजों का रणनीतिक भंडार तैयार कर लिया है और फिलिपींस और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के माध्यम से एक वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था का भी बंदोबस्त कर लिया है। भारत को भी इस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी, विशेषकर वर्ष 2000 में गलवान में चीन के साथ सैन्य झड़प के बाद उसे इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए था। अब भारत सरकार और कंपनियों ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है और यह दिख भी रहा है लेकिन इसमें तालमेल का अभाव दिख रहा है। सरकार ने 'काबिल' नाम से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्थापित की है जिसका उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखना है। इस बीच, वेदांत जैसी कुछ बड़ी कंपनियों और हैदराबाद स्थित मिडवेस्ट एडवांस्ड मटीरियल्स ने आपूर्ति व्यवस्था में भारी निवेश करना शुरू किया है।

हालांकि, इन प्रयासों को वास्तविक रणनीति का दर्जा नहीं दिया सकता। वास्तविक रणनीति आपूर्ति श्रृंखला में निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण दोनों का ख्याल रखने और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ काम करने के साथ ही जापान जैसे विश्वसनीय देशों को भी अपने साथ जोड़ने की होनी चाहिए। भारत की रणनीतिक सोच के साथ अक्सर सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि यह केवल आंतरिक बाजार पर ध्यान देता है। भारतीय कंपनियों भी प्रसंस्करण एवं निष्कर्षण में अग्रणी बन सकती हैं। प्रसंस्करण कार्यों के विस्तार में भारतीय इंजीनियर मानव पूंजी उपलब्ध करा सकते हैं। किंतु, इसके लिए सरकार से स्पष्ट संकेत एवं तालमेल की जरूरत होगी। इसके लिए विदेश नीति को लेकर भी सटीक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना होगा। उदाहरण के लिए चीन में जितनी मात्रा में खनिजों का निष्कर्षण होता है उसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी म्यांमार से आयात होता है। भारत ने ठीक अपने पड़ोस में इस संभावना को नजरअंदाज किया है मगर चीन ने ऐसा नहीं किया। भारत को यह भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि दुर्लभ खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण मेजबान देशों की मांगों के अनुरूप होगा। जैसे इंडोनेशिया यह मांग रख सकता है कि प्रसंस्करण उसके देश में ही होगा न कि भारत में। किसी भी रणनीति का प्रमुख उद्देश्य आपूर्ति व्यवस्था को जोखिम मुक्त रखना है, इसलिए भारत को यह शर्त स्वीकार होनी चाहिए।

अंत में, ऐसी किसी रणनीति में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बने जिसमें चीन पर निर्भर दूसरे देश भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए जापान जिस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला जोखिम मुक्त रखने की दिशा में काम कर रहा है वह भारत के लिए वित्तीय निवेश का एक स्रोत हो सकता है।

अजय मोहंती

भारत के लिए खुल रहे संभावनाओं के द्वार

भारतीय व्यापक आर्थिक नीति के कई पहलू अब स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस बारे में चर्चा कर रहे हैं अजय शाह

वृहद आर्थिक नीति दो प्रमुख विषयों के इर्द-गिर्द घूम रही है। इनमें पहला विषय दीर्घ अवधि से लगातार निजी निवेश में सुस्ती से जुड़ी समस्या है और दूसरा विषय वैश्विक अर्थव्यवस्था की सराहनीय प्रगति और इसमें भारत के भविष्य के लिए दिख रही बेहतर संभावना है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत दरों में कटौती कर सही दिशा में कदम उठाया है। एमपीसी के इस कदम को व्यापक नीति के बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत की आर्थिक तरक्की में सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू बड़ी एवं उच्च उत्पादन क्षमता वाली निजी कंपनियों का उदय है। इन कंपनियों का श्रम एवं पूंजी संसाधनों पर काफी हद तक नियंत्रण है। इसे देखते हुए भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए इन निजी कंपनियों की वृद्धि पर नजर रखना जरूरी है। बड़ी निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की सालाना रिपोर्ट में निवेश की थाह लेने का अच्छा मानक शुद्ध अचल परिसंपत्तियों की सालाना वृद्धि दर है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक शुद्ध अचल परिसंपत्तियों की औसत वृद्धि दर 6.6 फीसदी रही है। अगर 4 फीसदी मुद्रास्फीति पर विचार करें तो सालाना वास्तविक वृद्धि दर 2.6 फीसदी ही रह जाती है, जो भारत की सफलता के साथ मेल नहीं खाती है।

भारतीय निजी कंपनियों ने अपने निवेश की रफ्तार क्यों कम कर दी है? मोटे तौर पर कहा जाए तो इसके लिए केंद्रीय नियोजन एवं कानून-व्यवस्था जिम्मेदार है। कोई कारोबार खड़ा करने के लिए भावनात्मक ऊर्जा, समय, प्रयास, पूंजी सहित अन्य बातों की जरूरत होती है। जब बाहरी वातावरण बेतुका एवं अनावश्यक दबाव डालने लगते हैं तो निजी उद्यमी कारोबार खड़ा करने का अपना प्रयास रोक देते हैं। समाज का समाजवादी प्रारूप (जिसमें निजी कंपनियों में उत्पादों एवं प्रक्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है और सफल दावेदार के चयन में मनमाने अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है) अर्थव्यवस्था में सुस्ती लाता है यह इस व्यवस्था का मूल लक्षण है।

अगर ये परिस्थितियां ऐसी ही रहती हैं तो एक बेहतर वित्तीय वातावरण हालात संभालने में मददगार होगा। अगर ये जोखिम ऐसे ही बने रहते हैं तो भी कम लागत पर अधिक पूंजी उपलब्ध हो तो इससे ऊंचे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए एक दीर्घ उपाय पूंजी नियंत्रण तंत्र से जुड़ा हुआ है। भारत में पूंजी नियंत्रण समाप्त करना सदैव ही एक अच्छा विचार है क्योंकि इससे देश के भीतर पूंजी पर लागत कम हो जाती है। हाल के समय में इस तरह कुछ प्रयास किए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में इस दिशा में काफी कुछ किया जा सकता है।

इसके बाद मौद्रिक नीति की बारी आती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का मूल उद्देश्य यह है कि मुद्रास्फीति 4 फीसदी तक नियंत्रित रखा जाए। आरबीआई मुद्रास्फीति की दिशा निश्चित एवं स्थिर कर भारत की संपन्नता में अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर विचार करें तो आरबीआई मुद्रास्फीति में बड़ी कमी लाने में सफल रहा है। अगस्त 2020 से दिसंबर 2022 की अवधि में मुद्रास्फीति 6 फीसदी से घट कर वर्तमान समय में लगभग 4 फीसदी रह गई है। इसे देखते हुए नीतिगत दरों में कटौती तर्कसंगत लगती है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ इस तरह बदलाव हुआ है कि यह भारत के लिए नए अवसर लेकर आया है। हाल के घटनाक्रम ने चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र से दूर कर दिया है दिया है। वैश्विक कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सारा जोर लगा रही हैं। डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में दिक्कत शुरू होने से वैश्विक कंपनियां अब वैश्विक क्षमता केंद्रों और भारत जैसे देश में अनुबंध आधारित ढांचे की दिशा में पहल करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं।

लंबे समय तक मैं भारत को लेकर 'चीन प्लस वन' के दावे को लेकर सशंकित रहा हूं। मैंने अपना ध्यान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और वस्तुओं के निर्यात के आंकड़ों पर टिकाए रखा और पाया कि इनमें वास्तव में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। मगर अब भारत के लिए लाभ के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका को चीन से और भारत से अमेरिका को निर्यात इन दोनों के अनुपात पर नजर रखने की जरूरत है। मार्च 2025 में यह अनुपात 2.63 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया था। यह 2019 में 8 तक रहा है और धीरे-धीरे घटते हुए भारत के पक्ष में दिख रहा है। भारत के निर्यात को आंकने का एक अच्छा मानदंड वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात (पेट्रोलियम उत्पादों एवं सोना को छोड़कर) है। वर्ष 2022-24 के दौरान यह प्रति महीने लगभग 55 अरब डॉलर के स्तर पर स्थिर था। हाल में महीनों में कुछ वृद्धि दिखी है और यह प्रति महीने 70 अरब डॉलर के निकट पहुंच गया है। भारत में एफडीआई के आंकड़े कमजोर बने हुए हैं। भारत में एफडीआई के ठोस प्रदर्शन के बिना दीर्घकालिक सफलता के मार्ग की कल्पना करना मुश्किल है।

वैश्वीकरण की राह में आने वाली बाधाएं भारत को निर्यात के मोर्चे पर आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शुल्क एवं गैर-शुल्क बाधाएं भारतीय उत्पादकों के लिए कच्चा माल महंगा बना देती हैं। पूंजी नियंत्रण के कारण भारतीय उत्पादकों के लिए पूंजी महंगी हो जाती है और कई उद्योगों में पूंजी सबसे बड़ा कच्चा माल है। पिछले कई वर्षों में पहली बार हम इन मोर्चों पर लाभ मिलता दिख रहा है। भारतीय निर्यात में मजबूती के लिए यह अच्छा है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय व्यापार उदारीकरण का लाभ मिला।

भारतीय नीति निर्धारक पहले इस तरह के व्यापार समझौते नहीं कर पा रहे थे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ समझौतों में बड़ी व्यापार बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। कुछ महत्त्वपूर्ण देश जैसे ही व्यापार की राह में बाधाएं कम करेंगे वैसे ही दूसरे देशों के मामले में भी व्यापार बाधाएं कम होती जाएंगी। भारतीय व्यापार नीति चीन के वृहद आर्थिक संकट का लाभ उठाने पर केंद्रित होनी चाहिए और इसके साथ ही उसकी कंपनियों को भारत में सस्ते सामान खपाने से रोकने के प्रयास भी होने चाहिए। प्रत्येक व्यापार उदारीकरण वृहद आर्थिक हालात पर दबाव डालता है। शुल्क कम रहने से आयात मांग बढ़ती है जिससे व्यापार संतुलन की गुणवत्ता कम होती है। यह व्यापार घाटा संतुलन बहाली के लिए रुपये में कमजोरी को बढ़ावा दिया जाता है। घरेलू ब्याज दरें कम रहने से भी देश में पूंजी की आमद कम हो जाती है जिससे रुपया कमजोर होता है।

अगर भारत वैश्विक उत्पादन के केंद्र के रूप में सफल (शुल्क घटा कर, चीन और अमेरिका का एक मजबूत विकल्प बनकर और भारतीय पूंजी खाता विनियंत्रण के जरिये) होता है तो भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ सकता है और इससे ह्रास के कारणों का प्रभाव कम किया जा सकता है।

नीतिगत उपायों का इस्तेमाल अक्सर रुपये में गिरावट थामने के लिए किया जाता है। भारत के इतिहास का यह एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है जब सितारे भारत के पक्ष में दिख रहे हैं। वृहद आर्थिक नीति का श्रेष्ठ रुख व्यापार उदारीकरण, नरम मौद्रिक नीति, नीतिगत बुनियाद में सुधार (केंद्रीय नियोजन एवं कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं), पूंजी खाता विनियंत्रण और कमजोर रुपया इन सभी का मिश्रण है।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

दूरसंचार शुल्कों को दुरुस्त करने की जरूरत

आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की कहानी किसी को भी चकित कर सकती है। लेकिन, जुलाई 1995 में भारत में पहली मोबाइल कॉल किए जाने के 30 साल बाद क्या यह एक सुखद कहानी है? सबसे पहले, बात करते हैं संख्याओं की।

वैश्विक स्तर पर 9.1 अरब में से अकेले भारत में करीब 1.2 अरब मोबाइल सबस्क्राइबर हैं। भारत में इंटरनेट सबस्क्राइबर 97 करोड़ से ज्यादा हैं, जबकि दुनिया भर में यह संख्या 5.56 अरब है। भारत के ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर 94 करोड़ से ज्यादा हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर उनकी संख्या 5.3 अरब है।

हैंडसेट के मामले में भी आंकड़े उतने ही प्रभावशाली हैं। कुछ साल पहले तक देश में 75 फीसदी हैंडसेट आयात किए जाते थे और अब भारत 1.8 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात करने लगा है। यही नहीं भारत ने सालाना 1.8 अरब डिजिटल लेनदेन करके दुनिया को चौंका दिया है।

जैसा कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में एक साक्षात्कार में इस अखबार को बताया, भारत के दूरसंचार विकास की कहानी दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय बन गई है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उच्च ग्राहक संख्या और प्रभावशाली डिजिटल लेनदेन वॉल्यूम के साथ-साथ यहां टैरिफ भी बहुत कम हैं। मोबाइल कॉल दरें 10 साल पहले के 50 पैसे प्रति मिनट से घटकर लगभग 0.03 पैसे प्रति मिनट रह गई हैं। और डेटा की लागत 10 साल पहले के 287 रुपये प्रति जीबी से घटकर 9 रुपये प्रति जीबी रह गई है। औसत वैश्विक डेटा लागत 2.49 डॉलर प्रति जीबी के मुकाबले भारत की डेटा लागत महज 11 सेंट है। यह भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में भारी लाभ देता है।

हालांकि, सबसे सस्ती डेटा राजधानी (यह खिताब भारत निकट भविष्य में प्राप्त कर सकता है) होने की अपनी समस्याएं हैं। जब दूरसंचार कंपनियां लंबे समय तक शुल्क नहीं बढ़ा पातीं, तो समस्या होती है। जब 5जी डेटा और 4जी डेटा की कीमत समान होती है, तो समस्या होती है। जब उद्योग का कर्ज खरबों डॉलर में हो जाता है, तो समस्या होती है। जब प्रमुख दूरसंचार कंपनियां अपने लंबित बकाये को सरकारी इक्विटी में बदलना चाहती हैं, तो समस्या होती है। और जब उद्योग में इयाधिकार (ड्यूओपोली) को रोकना बोझ बन जाता है, तो समस्या होती है। ग्राहक संख्या और डेटा खपत में उच्च वृद्धि से परे देखें, तो भारतीय दूरसंचार कहानी तनाव की दर्शाती है। निजी दूरसंचार खिलाड़ियों की संख्या घटकर तीन रह गई है, और पिछले कुछ वर्षों से ड्यूओपोली का खतरा मंडरा रहा है। सरकार के पास निजी दूरसंचार कंपनियों में से एक - वोडाफोन आइडिया में 49 फीसदी हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाये में छूट की मांग वाली संयुक्त याचिका को खारिज करने के बाद कंपनी आगे की राहत के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

सामयिक सवाल
निवेदिता मुखर्जी

हालांकि सरकार वोडाफोन आइडिया में और अधिक इक्विटी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप से दूरसंचार कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में बदल देगा। फिर भी कंपनी किसी प्रकार की राहत की संभावना तलाशने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। चूंकि बैंक अब इस संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं और प्रमोटर आगे निवेश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सरकार की ओर से राहत का एक और दौर ड्यूओपोली को रोकने का अंतिम उपाय प्रतीत होता है। इस बीच, एक अन्य निजी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने भी अपने एजीआर बकाये पर राहत के लिए सरकार से संपर्क किया है। दूरसंचार विभाग ने अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया है। दूरसंचार क्षेत्र में अनिश्चितता को और बढ़ाने वाला एक कारक मौजूदा दूरसंचार कंपनियों और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में प्रस्तावित प्रवेशकों के बीच स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर टकराव है। दूरसंचार कंपनियों का तर्क है कि ट्राई की सिफारिश बराबरी के अवसर को नकारती है। दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम काफी प्रतिस्पर्धी नीलामी के जरिये मिला था। लेकिन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लेयरों को प्रशासित आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ट्राई ने स्पेक्ट्रम मूल्य के रूप में कंपनियों के एजीआर का 4 फीसदी सुझाया है।

भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बिना कनेक्शन वाले लोगों को जोड़ने में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है, और इसकी शुरुआत में किसी भी तरह की देरी से देश की दूरसंचार गाथा को नुकसान पहुंचेगा। भारत की मोबाइल टेलीफोनी की 30 साल की यात्रा में - उस दौर से जब मिस कॉल सबसे अच्छी चीज लगती थी, आज के ऐप के माध्यम से जीवन जीने के चलन तक - बड़ी संख्या में ग्राहकों और कम टैरिफ के बावजूद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को आंशिक रूप से ही पाटा जा सका है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी नो-गो डेटा जोन में आता है, जहां लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में समस्याएं हैं। ग्राम पंचायतों और गांवों को डेटा कनेक्शन प्रदान करने वाली सरकारी परियोजना भारतनेट से प्रगति की है, लेकिन अंतिम बिंदु तक पहुंच एक मसला बना हुआ है।

किसी भी चीज से ज्यादा, भारत की दूरसंचार कहानी में टैरिफ को दुरुस्त करने की जरूरत है। कम टैरिफ वास्तव में एक सीमा तक उपभोक्ताओं के लिए अच्छे हैं लेकिन वे उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं। अकेले 5जी पर दूरसंचार उद्योग ने खरबों डॉलर का निवेश किया है और उन्हें शायद ही कोई रिटर्न मिला हो। शुल्कों को युक्तिसंगत किए बिना, टेलीकॉम कंपनियां शायद वहां निवेश न करें जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यानी सेवा की गुणवत्ता में। यह पहले से ही खराब सिस्टम और कमजोर डेटा लिंक के मामले में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा रहा है।

आपका पक्ष

रेल यात्री सुविधाओं में सुधार की नई पहल

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों और परेशानियों को दूर करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अब रेल अधिकारी यात्रियों के साथ रेल कोच में सफर करेंगे। यह पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बीते वर्षों में भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें बंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों का परिचालन भी शामिल है, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक हुई है। हालांकि, टिकट बुकिंग से लेकर खान-पान तक की शिकायतें अभी भी बनी हुई हैं, जिनका जिक्र यात्री अक्सर सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। आरक्षित श्रेणी में तो यात्री टीटी से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सामान्य श्रेणी में सुनवाई में अक्सर देर होती है। रेलवे को टिकट आरक्षण से संबंधित परेशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए। तत्काल और सामान्य टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या टिकट खिड़की पर आने वाली दिक्कतों को लेकर आम शिकायतें हैं। भले ही रेलवे अपने ऑनलाइन सिस्टम को पारदर्शी बताता है, लेकिन पीक सीजन में बुकिंग में कई शिकायतें मिलती हैं। उम्मीद है कि जब अधिकारी यात्रियों के साथ सफर करेंगे, तो वे इन समस्याओं को देख पाएंगे और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

राजूराम प्रजापत, नागौर

मुंबई की लोकल ट्रेनों में पीक समय में भीड़ काफी बढ़ जाती है जिससे लोग दरवाजे पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं

साइबर सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत

हमारे देश में साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं। साइबर ठगों ने बैंकों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में साइबर ठगों ने राज्य सहकारी बैंक की एक शाखा का सर्वर हैक कर बैंक से करोड़ों रुपये लूट लिए। अगर साइबर चोर किसी बैंक को आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं तो ऐसे में आम आदमी की साइबर सुरक्षा कैसे होगी। कुछ समय पहले दिल्ली स्थित एम्स के सर्वर में साइबर अपराध करने वालों ने सेंध लगा दी। इससे वहां सर्वर से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हो गई थीं। देश में बढ़ते साइबर अपराध या धोखाधड़ी मामले के लिए साइबर क्राइम सेल को चुस्ती दिखानी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट हो

आज भी देश के अनेक सुदूर गांवों में उचित स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीणों को शहरों में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है, किंतु यह व्यवस्था तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती जब तक गांव स्तर पर आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त नहीं किया जाता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहिनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, लेकिन पूरे गांव की जिम्मेदारी केवल इन्हीं पर डालना व्यावहारिक नहीं है। प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आवश्यक है, जो प्राथमिक उपचार देने के साथ-साथ जरूरतमंद मरीजों को निकटतम सरकारी अस्पताल तक भेज सके। सरकार को गांवों में मेडिकल मोबाइल यूनिट की व्यवस्था करनी चाहिए, स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाने चाहिए।

सुभाष बुड़ाकन वाला, रतलाम

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अमेरिका के लॉस ऐंजलिस में आव्रजन के विरोध में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जलती कार के पास से अमेरिकी झंडा लेकर गुजरती युवती। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर मंगलवार को मरीन कोर के 700 और नैशनल गार्ड के 2,000 अतिरिक्त जवान लॉस ऐंजलिस रवाना हुए जिससे वहां सेना की मौजूदगी और बढ़ जाएगी।

मानवीय संकट

थुनबर्ग का अभियान

ग्रेटा थुनबर्ग गाज़ा में मानवीय संकट के प्रति दुनिया को जागरूक करने का अभियान चला रही हैं। ऐसे समय जब मौन रहने का अर्थ संलिप्तता हो सकती है, ग्रेटा थुनबर्ग एक बार फिर दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने जा रही हैं। इस बार जलवायु के बजाय मानवीय संकट उनके अभियान के केन्द्र में है। उनका नवीनतम कृत्य गाज़ा में इस्राइली नौसेना द्वारा आरोपित नाकेबंदी तत्काल तोड़ना है ताकि युद्ध, भूख और निराशा के शिकार क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। थुनबर्ग और 11 अन्य एक्टिविस्टों के साथ पालों से चलने वाले छोटे से जहाज मैडलीन ने सिसली से अपनी यात्रा शुरू की और उसका लक्ष्य न केवल सहायता देना, बल्कि उस पीड़ा का गवाह बनना है जो गाज़ा में आम हो गई है। गाज़ा पट्टी में दो मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं जो इस्राइली थलसेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा 2007 से नाकेबंदी का शिकार हैं। हमास पर लगाम लगाने के प्रयासों ने पिछले सालों में व्यवस्थित रूप से फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से दंड देने की व्यवस्था का रूप ले लिया है। इसमें सिविलियनों को सीमित आवागमन, आर्थिक ठहराव तथा लगातार बमबारी से निशाना बनाया जा रहा है।

इस्राइल और हमास के बीच जारी वर्तमान टकराव ने बार-बार गाज़ा की ढांचागत संरचना को खंडहर में बदला है, उसके लोगों को आघात पहुंचाया है तथा भविष्य को अनिश्चित किया है। 7 अक्टूबर, 2023 को इस्राइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद इस्राइल ने अपनी सैनिक आक्रामकता बढ़ा कर वहां लगभग तीन महीने से 'पूर्ण नाकेबंदी' की है। इस कालखंड में भोजन, ईंधन और दवाओं की सप्लाई लगभग पूरी तरह काट दी गई है। हालांकि, इसके बाद से थोड़ी बहुत सहायता पहुंची है, पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अकाल की आशंका जताई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ व अन्य मानवतावादी समूहों के अनुसार गाज़ा में बच्चे भूख का शिकार हैं, अस्पताल ध्वस्त हो रहे हैं तथा पूरा समुदाय स्वच्छ पानी से वंचित है। पूरी दुनिया में अपनी निर्भय जलवायु एक्टिविज्म के लिए विख्यात ग्रेटा थुनबर्ग ने उसी स्पष्टता और तात्कालिकता के साथ गाज़ा में मानवीय आपातस्थिति की ओर ध्यान दिया है। उनके साथी एक्टिविस्टों में ब्राजील की सोशल एक्टिविस्ट थियागो अविला और यूरोपीय संसद में फ्रांसीसी सदस्य रीमा हसन शामिल हैं। ग्रेटा नाकेबंदी तोड़ कर महत्वपूर्ण सप्लाई पहुंचाना चाहती हैं। उनकी यात्रा न केवल प्रतीकात्मक, बल्कि एक नैतिक खाली स्थान भरने का प्रयास है जहां दुनिया भर के राजनेता विफल हो गए हैं।

इस्राइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 'मैडलीन' को गाज़ा पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने थुनबर्ग और उनके साथी एक्टिविस्टों को 'यहूदी विरोधी' और 'हमास प्रचारक' बताया है। लेकिन मानवतावादियों को दुश्मन घोषित करने से गाज़ा में व्याप्त भयानक स्थिति समाप्त नहीं होती है। इसका अर्थ केवल इस्राइल द्वारा नाकेबंदी में मानवीय तत्वों का अभाव है। ग्रेटा थुनबर्ग के मिशन का राजनीति से सरोकार नहीं है, बल्कि यह केवल मानवतावादी सिद्धान्त से जुड़ा है। जब सरकारें पूरी जनसंख्या को मनुष्य समझने से इनकार कर दें तो सिविल सोसाइटी को सक्रिय होना पड़ता है। उनका पालों से चलने वाला जहाज वहां भोजन, दवायें और मानवीय गरिमा लेकर जा रहा है। यह सहायता से बढ़ कर इस बात का प्रतीक है कि दुनिया देख रही है और इस समय चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। उनका समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि वे ऐसा काम कर रही हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान करने में विफल रहे हैं। वे पीड़ित जनसंख्या को असली सहायता और असली सद्भावना देने के साथ ही उस पर ध्यान देने में विफल रही हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवीय सहायता कोई धमकी न हो कर एक अधिकार है। गाज़ा में एक पालों से चलने वाले जहाज से ग्रेटा थुनबर्ग की यात्रा केवल थोड़ी सी सप्लाई ले जाना नहीं है। इसका अर्थ साझा मानवीयता पर जोर देना है। इसका अर्थ निष्क्रियता को 'न' कहना है। इस नैतिक संघर्ष में हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ हमास जैसे आतंकी संगठनों का समूल अंत भी जरूरी है।

भारत की कुशल श्रमशक्ति

विकसित दुनिया को इस समय पूंजी के बजाय कुशल, गतिशील व उत्साही लोगों की आवश्यकता है। भारत अपनी युवा व कुशल श्रमशक्ति से यह जरूरत पूरी कर सकता है। इसके लिए व्यापक कौशल प्रशिक्षण जरूरी है।

दिनेश सूद

(लेखक, कौशल विकास से संबद्ध हैं)

वर्ष 2030 तक दुनिया को श्रमशक्ति की अभूतपूर्व कमी का शिकार होना पड़ सकता है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह कमी 50 मिलियन तक हो सकती है। एक हालिया 'ग्लोबल असेस टु टैलेंट फाम इंडिया'-गति फाउंडेशन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह कमी 2050 तक 250 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसका कारण बुढ़ाती जनसंख्या, घटती प्रजनन दर तथा संकुचित होती घरेलू श्रमशक्ति है। हालांकि, स्वचालीकरण और कृत्रिम बुद्धि-एआई कुछ समाधान दे सकते हैं, लेकिन तकनीकी परिवर्तन की गति मानव पूंजी की मांग के साथ मेल नहीं खा सकती है। बुढ़ाती जनसंख्या वाली औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में कुशल श्रमशक्ति की मांग बढ़ती रहेगी। इस संदर्भ में भारत 900 मिलियन से अधिक काम करने की आयु वाले लोगों के साथ 'जनसंख्या लाभांश' की स्थिति में है। इसे अक्सर हमारी सबसे बड़ी पूंजी के साथ ही जनसंख्या के बोझ के रूप में भी देखा जाता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए कुशल और अर्धकुशल श्रमशक्ति का विकास करना जरूरी है।

भारत की जनता में परिवर्तनशीलता और नए कौशल प्राप्त करने की क्षमता इस दिशा में महत्वपूर्ण समाधान पेश कर सकती है। भारत हर साल अपने कार्यबल के लगभग 700,000 लोगों को विदेश भेजता है। मुख्य रूप से वे स्वास्थ्यरक्षा, परिवहन, तकनीक और अतिथि सत्कार क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन एक समन्वित राष्ट्रीय योजना के साथ यह संख्या हर साल बढ़ा कर 2.5 मिलियन की जा सकती है। भारत के श्रमबल निर्यात में इस वृद्धि से न केवल वैश्विक मांग पूरी करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे हर साल विदेशों से आने वाली मुद्रा बढ़ कर 300 बिलियन डालर पहुंच सकती है। भारत वर्तमान समय में प्रति वर्ष अपनी श्रमशक्ति के माध्यम से 129 बिलियन डालर लाने से दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। इस प्रकार विदेशों में रोजगार भारत की वैश्विक पहुंच में महत्वपूर्ण योगदान करेगा और इससे दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा।

'गति' रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 20 देश विश्व श्रमबल में कमी का 90 प्रतिशत अनुभव कर रहे हैं। अमेरिका में 11 से 12 मिलियन अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता है और इसके बाद 5-6 मिलियन के साथ ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, हंगरी और चेक गणराज्य में प्रत्येक में 4-5 मिलियन कामगारों की कमी है। जर्मनी और रूस में प्रत्येक में 3-4 मिलियन तथा जापान में 2-3 मिलियन कामगारों की आवश्यकता है। अन्य देशों में कनाडा, आस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, ताइवान, नीदरलैंड, आस्ट्रिया और इटली हैं जिनमें से प्रत्येक में 1-2 मिलियन कामगारों की आवश्यकता है। इसके साथ ही छोटे पर उच्च आय वाले देशों जैसे सिंगापुर, रोमानिया, बुल्गारिया और हांगकांग में 0.5 से 1 मिलियन कामगारों की कमी अनुभव की जा रही है। यह मांग पूरी तरह स्पष्ट है और भारत इस मांग को पूरी करने का प्रयास कर रहा है। कम से अधिक कौशल वाले सभी प्रकार के कामगारों की मांग है। अनुमानित वैश्विक मांग में 70 प्रतिशत कम एवं मझोले कौशल वाले कामों की है। इनमें लगभग 18 से 20 मिलियन कम कौशल वाले पद, 6-8 मझोले कौशल वाले पद तथा 10-12 मिलियन उच्च कौशल वाले पद हैं। इसलिए भारत की नीतियों में इस मांग की संरचना के अनुसार श्रमबलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनौती विदेशों में ज्यादा कामगार भेजने की नहीं, बल्कि सही कौशल वाले लोगों को सही स्थानों और सही उद्योगों में भेजने की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रवासन के लिए नए दृष्टिकोण में तीन प्रमुख रणनीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इनमें वैश्विक मांग पूरी करना, घरेलू सप्लाई में सुधार करना और एक दृढ़ व दीर्घकालीन प्रवासन इकोसिस्टम तैयार करना शामिल हैं।

भारत को कौशल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मांगों के संबंध में भारत को सक्रिय रूप से लक्षित देशों को साथ लेना चाहिए ताकि कौशल प्रमाणपत्रों में सामंजस्य बिठा कर परस्पर स्वीकृति समझौतों को लागू किया जा सके। सप्लाई पक्ष में कौशल बढ़ाने के लिए भारत को महत्वपूर्ण रूप से तकनीकी शिक्षा, साफ्ट कौशल और विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यह बात खासकर जापान और जर्मनी जैसे देशों पर लागू होती है क्योंकि वहां भाषा में प्रवाह आवश्यक है। इन बाधाओं को पार करने में शामिल प्रमुख रणनीतियों में स्कूल स्तर पर भाषा शिक्षण, उद्योग-केन्द्रित प्रशिक्षण तथा सक्षम शिकायत निवारण व्यवस्थायें शामिल हैं। कुछ अग्रगामी सोच वाली राज्य सरकारों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों में जापानी भाषा सीखने का विकल्प दिया गया है तथा तेलंगाना ने 'रिटर्नी इंटीग्रेशन प्रोग्राम' चलाए हैं। लेकिन इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना जरूरी है जिसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा समन्वय शामिल हैं। समय आ गया है कि भारत वैश्विक श्रमशक्ति परिवर्तन पर केन्द्रित एक केन्द्रीकृत एजेंसी का गठन करे। यह फिलीपीन्स के डिपार्टमेंट आफ माइग्रेंट वर्कर्स या बांग्लादेश में ब्यूरो आफ मैनपावर इम्प्लायमेंट एंड ट्रेनिंग की तरह हो सकता है। ऐसे संगठन में सभी पक्षों को एकसाथ लाया जा सकता है जिनमें मंत्रालय, राज्य सरकारें, कौशल परिषदें, भर्ती एजेंसियां और उद्योग संस्थान शामिल हैं। ऐसी संस्था भर्ती में समन्वय, सुनिश्चित नैतिक प्रवासन व्यवहार तथा वैश्विक मांग पर तुरन्त निगरानी कर सकती है। समान रूप से खासकर कम और मध्यआय वर्ग वाले कामगारों के लिए प्रवासन में सहायता हेतु वित्तीय समर्थन विकल्पों को विकसित करना महत्वपूर्ण है।

देश को ऐसी कल्याण व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जो विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों को सुरक्षा दे सके तथा वहां से वापस आने वालों की शिकायत निवारण और उनको अर्थव्यवस्था में पुनः समाहित करने का काम कर सके। इसके साथ ही लगातार भारतीय प्रतिभा के लिए उच्च मांग वाले क्षेत्रों की लगातार खोज कर उन पर ध्यान देना जरूरी है। परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण रहे स्वास्थ्यरक्षा, अतिथि सत्कार, घरेलू कामकाज और लाजिस्टिक्स के साथ ही भारत को उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 'हरित रोजगार', ढांचागत संरचनाओं का विकास, डिजिटल सार्वजनिक कल्याण तथा टिकाऊ विकास संबंधी स्टार्टअप शामिल हैं जहां दुनिया भर में कौशल की भारी कमी अनुभव की जा रही है।

प्रवासन की बाधायें समझना भी जरूरी है। इस क्षेत्र में प्रगति के बावजूद अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं। अक्सर भारत में प्राप्त योग्यताओं को वैश्विक स्तर पर पहचाना नहीं जाता है जिससे कामगारों को प्रवासन पर भारी खर्च के साथ ही संदिग्ध एजेंटों द्वारा शोषण का जोखिम भी उठाना पड़ता है। प्रवासन को केन्द्र में रखने वाला विमर्श राजनीतिक रूप से अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में विवाद का कारण है। यहां अधिकांश विपक्षी पार्टियां अवैध आप्रवास पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। लेकिन कुशल, सुनियोजित तथा विधिक प्रवासन अधिकांश विकसित देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसका कारण सद्भावना के बजाय आर्थिक जरूरतें हैं। इन देशों को अपनी प्रगति बनाए रखने के लिए समुचित संख्या में कुशल कामगारों की जरूरत है जो बुढ़ाती जनसंख्या की सहायता कर महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवायें बनाए रख सकें। इस क्षेत्र में भारत अपनी युवा जनसंख्या और प्रशिक्षण ढांचे के विस्तार के साथ विश्वसनीय वैश्विक साझीदार के रूप में उभर सकता है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण राजनयिक पहलें की गई हैं।

उदाहरण के लिए जर्मनी, कुशल कामगार वीसा कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जबकि जापान ने भारतीयों के लिए उपलब्ध अप्रेंटिसशिप वीसा की श्रेणियां बढ़ाई हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों से इस बारे में वार्ता जारी है कि वे भारतीय ड्राइविंग लाइसेंसों को स्वीकार करें। इस बीच भारत ने आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, डेनमार्क, इटली और ब्रिटेन के साथ सरकारी स्तर पर प्रवासन समझौते किए हैं। भारत ने इस्राइल से भी सरकारी स्तर पर अनुबंध किया है। युवा पेशेवर योजना के अंतर्गत हर साल 3000 भारतीय ब्रिटेन में दो साल पढ़ने और काम करने के लिए जा सकते हैं। भारत अपनी युवा जनसंख्या तथा उपयुक्त और व्यापक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर में विश्वसनीय, प्रशिक्षित व सशक्त व्यक्तियों के प्रवासन का केन्द्र बन सकता है। भारत में प्रगति की अगले लहर पूंजी या वस्तुओं के बजाय सक्षम कामगारों द्वारा निर्धारित होगी।

बिजनेस का भविष्य और महिलाएं

> देश के शीर्ष 10 बिजनेस स्कूलों ने बताया है कि उनके 2024 के एमबीए समूहों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक महिलाएं हैं।

आशीष मुंजाल

(लेखक, सनस्टोन के सीईओ हैं)

भारत अपने शैक्षिक और व्यावसायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख रहा है, जिसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और वे कॉर्पोरेट जगत में शीर्ष नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे बढ़ रही हैं। यह बदलाव न केवल पिछले रुझानों से एक स्वागत योग्य प्रस्थान है, बल्कि भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक समावेशी और गतिशील भविष्य का संकेत भी देता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान रही है।

हालांकि, हालिया डेटा एमबीए कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार और पर्याप्त वृद्धि को उजागर करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुसार, 2022-23 शैक्षणिक वर्ष में कुल एमबीए नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 42.11 प्रतिशत थी - जो 2018-19 में 33 प्रतिशत से एक प्रभावशाली छलांग है। कच्चे आंकड़ों में, यह 2018-19 में 78,374 महिलाओं से 2022-23 में 1,20,142 तक की छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। देश के शीर्ष 10 बिजनेस स्कूलों ने बताया है कि उनके 2024 के एमबीए समूहों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक महिलाएं हैं, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यहां तक कि राज्य स्तर पर, जैसे कि महाराष्ट्र में, बदलाव स्पष्ट है।

राज्य के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) सेल के आंकड़ों के अनुसार, अब सभी एमबीए छात्रों में से लगभग आधी महिलाएं हैं - एक उल्लेखनीय वृद्धि। जबकि मेट्रो शहर महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा में अग्रणी हैं, टियर 2 और टियर 3 शहर भी पीछे नहीं हैं। भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2023 में उल्लेख किया गया है कि इंदौर, नासिक

और कोयंबटूर जैसे शहरों में 2020 से एमबीए कार्यक्रमों में महिलाओं के नामांकन में 27 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। क्षेत्रीय बिजनेस स्कूल इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच को भी लोकतांत्रिक बना दिया है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 और 2023 के बीच, गैर-मेट्रो शहरों में महिलाओं द्वारा ऑनलाइन एमबीए नामांकन में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं को स्थानांतरित हुए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिली है - जो कई लोगों के लिए एक आवश्यक विचार है। इस सकारात्मक प्रवृत्ति में कई कारकों ने योगदान दिया है।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक सशक्तिकरण। एमबीए को तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता और करियर उन्नति के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है, जो महिलाओं को पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को तोड़ने में सक्षम बनाता है। दूसरा, बिजनेस स्कूल अधिक समावेशी होते जा रहे हैं। कई संस्थान अब महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए छात्रवृत्ति, मेंटरशिप प्रोग्राम और लचीले शिक्षण विकल्प प्रदान करते हैं। वित्तपोषण में नवाचार के लिए भी उल्लेखनीय जोर है, विशेष रूप से टियर 2-3 क्षेत्रों के छात्रों के लिए, जिसमें अनुकूलित छात्रवृत्ति योजनाएं और चरणबद्ध शुल्क भुगतान योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार और कॉर्पोरेट पहल इस बदलाव को बढ़ावा दे रही हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम कमाने वाले परिवारों से पेशेवर पाठ्यक्रम करने वाली लड़कियों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क माफ़ी की शुरुआत की - इस कदम से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एमबीए कार्यक्रमों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी व्यापार जगत में वास्तविक प्रभाव में तब्दील हो रही है। महिला एमबीए स्नातक वित्त से लेकर तकनीक तक के उद्योगों में अपनी पहचान बना रही हैं। संस्थागत निवेशक सलाहकार सेवाओं (आईआईएएस) के एक अध्ययन से पता चला है कि शीर्ष 500 एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में महिलाएं अब 18 प्रतिशत बोर्ड पदों पर काबिज हैं। इन फर्मों में 22 महिला बोर्ड अध्यक्ष, 25 महिला सीईओ और 62 महिलाएं कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा, महिलाएं प्लेसमेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। डेटा दर्शाता है कि महिला एमबीए स्नातकों की उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में 36.7 प्रतिशत अधिक चयन दर है, जो उनकी तैयारी और उद्योग प्रासंगिकता को दर्शाता है। एमबीए करने वाली महिलाओं में उद्यमिता में भी उछाल देखा जा रहा है।

औपचारिक प्रशिक्षण और एक नए दृष्टिकोण से लैस, कई संगठनों को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए, जैसे समान वेतन, भेदभाव विरोधी प्रथाएँ और पारदर्शी पदोन्नति। महिलाओं को मार्गदर्शन और रोल मॉडल प्रदान करने के लिए मेंटरशिप नेटवर्क विकसित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, लचीली कार्य व्यवस्था पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी।

आप की बात

मोदी की उपलब्धियां

पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने विकासात्मक एजेंडा में बड़े कदम उठाए फिर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल, रोजगार व सामाजिक समावेशन में कमी और पारदर्शिता की चुनौतियां को लेकन विपक्ष हमेशा हावी होता आया हैं। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन वर्षों में जन विश्वास कायम करने के साथ अनेक निर्णायक कदम उठाए हैं। आर्थिक सुधारों से लेकर डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और जनधन योजना जैसे कार्यक्रमों ने समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। विदेश नीति में भी भारत की वैश्विक साख में वृद्धि देखी गई है। सरकार ने धारा 370 का खात्मा, तीन तलाक कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर साहसिक निर्णय लिए हैं जो व्यापक जन विमर्श का विषय बने। हालांकि, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता महंगाई और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन सरकार ने इनको यथासंभव दूर करने का प्रयास किया है और वह उसमें काफी सीमा तक सफल भी रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की उपलब्धियां निश्चित रूप से उल्लेखनीय हैं और उससे उम्मीद है कि वह भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।

- **अमृतलाल मारू**, इंदौर

शिक्षकों की कमी

भारत को ज्ञान-आधारित आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा व्यवस्था की आत्मा-शिक्षक को केंद्र में रखना होगा। वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी मात्र संख्या का संकट नहीं, बल्कि विचार, गुणवत्ता और नवाचार का नुकसान है। संसद में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ही 5,410 पद रिक्त हैं और अनेक संस्थानों में 40 प्रतिशत से अधिक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। यह स्थिति शिक्षा के स्तर, अनुसंधान की गुणवत्ता और छात्र-हित की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित कर रही है। शिक्षण संस्थानों में ज्ञान का सृजन तभी संभव है जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों के प्रति प्रेरित, प्रशिक्षित और समर्पित हों। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अत्यंत जटिल, धीमी और प्रशासनिक अड़चनों से घिरी हुई है। इसके समाधान हेतु एक केन्द्रीय शिक्षक चयन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो पारदर्शी, समयबद्ध और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर स्थायी पदों पर नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षक पेशे को आकर्षक बनाने

- **अवनीश कुमार गुप्ता**, आजमगढ़

चेतावनी और अवसर

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जारी संकट और चीन की तेज़ी से बढ़ती शोध शक्ति भारत के लिए एक चेतावनी और अवसर दोनों है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान न पाना स्पष्ट करता है कि हमारे शैक्षिक ढांचे में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। जब चीन के पाँच विश्वविद्यालय इस सूची में आ सकते हैंए तो भारत के क्यों नहीं? इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध जैसे अति-गुणवत्ता निर्भर क्षेत्रों में भी जातिगत आरक्षण लागू है। इससे अक्सर मेधावी और मेहनती छात्र अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जब चयन की प्रक्रिया में 100 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 40 अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से पिछड़ जाता है तो यह गुणवत्ता के साथ अन्याय है। इसके फलस्वरूप, खासकर हमारे विश्वविद्यालयों के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान की गुणवत्ता और नवाचार का स्तर गिरता है। इसके परिणामस्वरूप अमीर और उच्च मध्यवर्ग के प्रतिभाशाली छात्र देश छोड़कर उन जगहों पर जाते हैं जहां उन्हें समान अवसर और मूल्यांकन की निष्पक्षता मिलती है। इस दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा में आरक्षण की समुचित समीक्षा होनी चाहिए।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

हिंसक प्रवृत्ति

नारी सशक्तीकरण के नाम पर रिश्तों को तार-तार करने का हिंसक चलन विचारणीय है। छिपकली से भी डरने वाली कुछ लड़कियाँ आखिर इतनी निडर कैसे हो गई कि अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतारने से भी नहीं कतराती । कभी भाड़े के हत्यारों को बुलाकर अपने पति की हत्या की साजिश रचती हैं। पति को सुनसान जंगल में ले जाकर मौत के हवाले कर शव को खाई में फेंकती हैं तथा कभी कत्ल करके शव को किसी ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से पत्थर बनाने का असफल प्रयास करती हैं। कोई अपने प्रेमी के साथ पति का गला घोंटकर शव के ऊपर साँप को बिठाकर पति की मौत का कारण साँप के द्वारा डँसा जाना बताती हैं। कोई विवाह के बाद से ही पति की कमाई पर कब्जा करके अपने मायके वालों का पोषण करती हैं तथा पति को आतंकित करके मृत्यु का वरण करने हेतु विवश कर देती है। मेघालय में हनीमून ट्रिप पर गई नव विवाहिता सोनम की कहानी भी पुरानी कहानियों से इतर प्रतीत नही होती। यह पति के साथ ही विवाह जैसी संस्था में व्यक्त विश्वास का भी कत्ल है जिसे समय के साथ भुला दिया जाएगा।

- **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

हमें भाईचारे के साथ एक साथ रहना चाहिए या मूर्खों की तरह एक साथ नष्ट हो जाना चाहिए? - मार्टिन लूथर किंग, जूनियर

भाजपा ग्यारह वर्ष की उपलब्धियों को स्वाभाविक रूप से अपने अंदाज में उत्सव के रूप में मनाएगी, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह देखना रोचक होगा कि भाजपा अपनी उपलब्धियों को किस तरह से जनता तक पहुंचा पाती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका क्या उत्तर तलाशता है।

उपलब्धियां भी, चुनौतियां भी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के ग्यारह वर्ष परिवर्तन और प्रगति के प्रतीक तो रहे ही, इस दौरान देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव भी देखे। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा, अनुच्छेद-370 हटाना, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे साहसिक फैसले लिए गए, तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना तमाम चुनौतियों के बावजूद एक उपलब्धि रही। मेक इन इंडिया जैसी पहल ने भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया, तो डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। पिछले करीब 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग घनघोर गरीबी के जाल से तो मुक्त हुए ही हैं, मुद्रास्फीति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, जो 2013-14 में 9.4 फीसदी से घटकर आज 4.6 फीसदी रह गई है। इसके अतिरिक्त, करीब चार लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण से ग्रामीण भारत का 99 फीसदी हिस्सा राष्ट्रीय नेटवर्क में आ गया है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। विश्व बैंक का यह कहना भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में छह वर्षों में जो हासिल किया है, उसमें आम तौर पर दशकों लग जाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा में भारत की प्रगति ने वैश्विक स्तर पर सराहना बटोरी है, तो दूसरी तरफ, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम आवास और जनधन जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाया है। नई शिक्षा नीति और स्किल इंडिया जैसे कदम शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। पड़ोसी प्रथम नीति और क्वाड जैसे गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी और जी-20 जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका ने देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा किया है। हालांकि इनके बीच बेरोजगारी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पर्यावरणीय समस्याएं और असमानता को दूर करने जैसी चुनौतियां भी हैं, जिन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा ग्यारह वर्ष की उपलब्धियों को स्वाभाविक ही अपने अंदाज में उत्सव के रूप में मनाएगी। नौ जून से शुरू हुआ भाजपा का देशव्यापी जनसंपर्क अभियान उसके उत्सव का ही हिस्सा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तीन तलाक, जातिगत आरक्षण और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी अपनी उपलब्धियों को पेश करेगी। लेकिन बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव, जो अक्तूबर-नवंबर 2025 में होने हैं, के मद्देनजर यह देखना रोचक होगा कि भाजपा अपनी उपलब्धियों को किस तरह से जनता तक पहुंचा पाती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका क्या उत्तर तलाशता है।

इमोशन, ड्रामा और ट्रेजडी

अमेरिकी राष्ट्रपतियों और व्यवसायियों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव का इतिहास रहा है। ट्रंप और मस्क जिन दुनियाओं से आते हैं, उन्हें देखते हुए माना ही जा रहा था कि बिखरना इस जोड़ी की नियति है। दोनों के बयान बेशक सुर्खियां बन रहे हों, पर राजनीति बलिदान मांगती है, इस रिश्ते का सच यही है।

उन्नीस सौ सत्तर के दशक में शोले नामक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, जिसमें एक वाटर टैंक के शीर्ष पर बैठे धर्मेंद्र गांव वालों से कहते हैं, 'इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजडी है।' ट्रंप बनाम मस्क विवाद में यह सब तो है ही, और भी बहुत कुछ है–धन के खिलाफ सत्ता का मुकाबला और अविश्वास का तूफान। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति के बीच लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति ने जहर उगलने के लिए हर तरह के मंच का इस्तेमाल किया, जिसने लाखों लोगों को आकर्षित किया और 'आई हेट माई एक्स' से लेकर 'ट्रंप अब एलन का एक्स है' तक के चुटकुले पोस्ट किए गए। कुछ दिनों पहले तक दोनों एक-दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मस्क ने ट्वीट किया था, 'मैं ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं, जितना एक सीधा-सादा आदमी दूसरे आदमी से कर सकता है।' ट्रंप ने मस्क को 'दुनिया के सबसे महान व्यापारिक नेताओं और नवप्रवर्तकों में से एक' बताया।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

लेकिन बृहस्पतिवार की रात तक, दोनों का करीबी रिश्ता असहमति से कटु आलोचना में बदल गया। मस्क का मिजाज नाराजगी से बढ़कर बगावत में बदल गया। उन्होंने दावा किया कि उनके बिना ट्रंप हार जाते। उन्होंने कहा कि दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन मामले से जुड़ी फाइलें कभी सार्वजनिक नहीं की गईं, क्योंकि उनमें ट्रंप का नाम था और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की। ट्रंप ने न सिर्फ निराशा जताई, बल्कि संघीय निधि में कटौती की धमकी से लेकर यहां तक कहा कि एलन ने 'अपना दिमाग खो दिया है।' देर रात तक, वार्ताकार दोनों से सुलह करने का आग्रह कर रहे थे।

अमेरिकी थ्रिलर सीरीज *हाउस ऑफ कार्ड्स* में फ्रैंक अंडरवुड कहते हैं, 'सत्ता रियल एस्टेट है, जहां लोकेशन ही सब कुछ है। स्रोत के जितना करीब, मूल्य उतना ऊंचा।' आठ नवंबर को टेस्ला के शेयर का मूल्यांकन 10 खरब डॉलर के आंकड़े को छू गया था, क्योंकि मस्क को ट्रंप की सत्ता में वापसी का लाभार्थी माना जा रहा था। जब उन्होंने ट्रंप से दूरी बना ली, टेस्ला के शेयर में 14 प्रतिशत से अधिक और बाजार मूल्य में 150 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई। जनवरी और जून के बीच, स्टॉक 426 डॉलर से गिरकर 284 डॉलर पर आ गया।

इतिहास गवाह है : सत्ता धन पर भारी पड़ती है। 1934 में प्रतिष्ठित अमेरिकियों के एक समूह ने अमेरिकन लिबर्टी लीग की स्थापना की। उनका उद्देश्य था : राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रस्तुत न्यू डील का विरोध करना। लीग ने न्यू डील को समाजवादी और फासीवादी, दोनों ही रूप में निरूपित किया। 1936 में अपने पुनर्निर्वाचन अभियान में रूजवेल्ट ने लीग पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें 'आर्थिक राजतंत्रवादी' कहा। उन्होंने धन शक्ति के 'वॉल स्ट्रीट तख्तापलट' को हराया और फिर से चुने गए। रूजवेल्ट अकेले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं थे, जिन्हें मित्र से शत्रु बने लोगों का सामना करना पड़ा। टेड रूजवेल्ट का जॉन रॉकफेलर से स्टैंडर्ड ऑयल के विघटन को लेकर मतभेद हो गया था। हेनरी फोर्ड और वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्वयुद्ध में अमेरिकी तटस्थता से अलग होने से पहले वेतन नीतियों पर सहयोग किया था। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट, जिन्होंने 'अमेरिका फर्स्ट' को लोकप्रिय बनाया, लगातार राष्ट्रपतियों के साथ लड़े। रॉस पेरोट ने रोनाल्ड रीगन की नीतियों का विरोध किया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एनएएफटीए) ने जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और सरकारी खर्च को लेकर बिल क्लिंटन की आलोचना की।

इन विवादों के बावजूद शासन-प्रशासन ट्रेजरी सचिव के रूप में व्यवसायियों को चुनते रहे। जैसा कि कहा जाता है, ट्रंप-मस्क के रिश्ते का टूटना नियति में लिखा था। दोनों अलग-अलग समय क्षेत्रों में अलग-अलग दुनिया से हैं, और खुद के प्रति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। यकीनन, यह एक ऐसी साझेदारी थी, जो लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। ईरान-इराक युद्ध के दौरान हेनरी किसिंजर ने कहा था, 'यह अफसोस की बात है कि दोनों पक्ष हार नहीं सकते।' जैसे-जैसे विवाद बढ़ता गया, व्लादिमीर पुतिन द्वारा दोनों के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत की पेशकश के मीम्स सामने आने लगे।

मस्क शुरू से ट्रंप समर्थक नहीं थे। याद रखें कि वाशिंगटन के गलियारों में मस्क का पहला कदम ओबामा युग में पड़ा था, जब 2009 में अमेरिकी रिकवरी और पुनर्निवेश अधिनियम लागू किया गया था। मस्क ने कैलिफोर्निया में अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए 46.5 करोड़ डॉलर के संघीय ऋण का इस्तेमाल किया और स्पेसएक्स ने तब ध्यान आकर्षित किया, जब ओबामा ने फ्लोरिडा में उसके दफ्तर का दौरा किया। दरअसल, मस्क 2016 में भी ट्रंप के समर्थक नहीं थे; वह ट्रंप मीडिया ग्रुप को खत्म करने के प्रयास के बाद 2024 में ही जुड़ पाए। मस्क ने ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को 29 करोड़ डॉलर से अधिक का दान दिया और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग ट्रंप के अभियान को समर्थन देने के लिए किया।

सच कहें, तो मस्क कभी अपनी बात या राय नहीं छिपाते हैं। टैरिफ ट्रंपोनॉमिक्स का मुख्य आधार है और मस्क कभी भी उच्च टैरिफ से सहमत नहीं थे। सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने और सीनेटरों को वित्त पोषित करने के बाद, मस्क का मानना था कि ऋण और घाटे, तथा 'बिग, ब्यूटीफुल बिल' पर उनकी राय ली जानी चाहिए। जब उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें बाहर कर दिया गया, तो मस्क ने बिल को 'घृणित' कहना शुरू कर दिया और इसे खत्म करने के लिए अभियान चलाया। एक बाहरी व्यक्ति जो ट्रंप खेमे में अपनी जगह बना पाया, आज वास्तव में फिर से बाहर है।

राजनीतिज्ञ-व्यवसायी गठजोड़ और उसके परिणाम की गाथा न तो नई है और न ही जल्दी समाप्त होने वाली है। ट्रंप बनाम मस्क की लड़ाई किस तरह आगे बढ़ेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रंप ने कहा कि वे लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं और बातचीत करने के मूड में नहीं हैं। इस बीच, एपस्टीन के आरोप और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग संबंधी पोस्ट पर मस्क के ट्वीट को उनकी टाइमलाइन से हटा दिया गया। यह प्रकरण तकनीक जगत और अन्य क्षेत्र के दिग्गजों के लिए एक उपयोगी सबक है। जैसा कि माइकल डॉब्स ने *हाउस ऑफ कार्ड्स* में कहा है, 'राजनीति बलिदान मांगती है—यकीनन, दूसरों का।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

नेपोलियन हिल

बिखरे हुए विचार परिणाम नहीं देते। इसलिए, अपने विचारों और लक्ष्यों को लिखें, योजनाएं बनाएं और उन्हें लगातार परिष्कृत करें। 'ध्यान' उस पर केंद्रित रखें, जिसे आप चाहते हैं, न कि उस पर जो गैर-जरूरी हो।

मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता है

मनुष्य का मन जो कुछ सोचता है और उस पर दृढ़ विश्वास करता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। धैर्य, दृढ़ता और परिश्रम सफलता का एक अपराजेय संयोजन बनाते हैं। सभी शारीरिक क्रियाओं का प्रारंभ विचार के रूप में होता है। शारीरिक क्रिया पर नियंत्रण के लिए पहले उस विचार को नियंत्रित करना आवश्यक है जो इसे प्रेरित करता है। जीवन में सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट, कल्पनाशील दृष्टि से होती है कि व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता है। रचनात्मक दृष्टि दिवास्वप्न से परे है, अर्थात केवल किसी कार्य के बारे में सोचने से भिन्न है। यह केवल ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि इसमें एक प्रबल इच्छा और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट मानसिक तस्वीर शामिल है। विचार वास्तविकता के बीज हैं। रचनात्मक दृष्टि को पोषित करके व्यक्ति अवसरों को पहचान सकता है और निर्णायक रूप से कार्य कर सकता है। जैसे हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने के लिए रचनात्मक दृष्टि का उपयोग किया। 'सोचने की शक्ति 'मानसिक डायनामाइट' है, जिसे संगठित और रचनात्मक रूप से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है।' विचारों को कार्य योजना में ढालना आवश्यक है। बिखरे हुए विचार परिणाम नहीं देते। इसलिए, अपने विचारों और लक्ष्यों को लिखें, योजनाएं बनाएं और उन्हें लगातार परिष्कृत करें। अपना 'ध्यान' जीवन में उस पर केंद्रित रखें, जिसे आप चाहते हैं, न कि उस पर जो गैर जरूरी चीज हो। यह अनुशासित दृष्टिकोण मन को बाहरी प्रभावों या अनिर्णय से बचाता है। आपके पास केवल एक चीज पर पूर्ण नियंत्रण है, वह है आपके विचार। आप जहां से शुरू करते हैं, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं, उसे बदल सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या करने जा रहे हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। हमारा विचार ईश्वरीय उपहार है, जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो आप किसी अन्य चीज को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। नियंत्रित ध्यान मस्तिष्क को व्यक्ति के प्रमुख विचारों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति चुंबकीय बनाता है, जिससे वह हमेशा अपनी प्रमुख सोच से संबंधित हर आवश्यक चीज की खोज में रहता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि परिस्थितियों का निर्माता है। वह अपनी परिस्थितियां और अवसर स्वयं बनाता है। लोगों के जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने मित्रों, परिवार और पड़ोसियों की बातें सुनते हैं, लेकिन स्वयं को जल्दी नहीं सुन पाते। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जो 'अनंत बुद्धि' से जुड़कर इच्छाओं को साकार कर सकता है। आपके पास अपना मस्तिष्क और मन है। इसका उपयोग करें और अपने निर्णय स्वयं लें। जब आप नकारात्मक विचारों के लिए अपने मन का द्वार बंद कर देते हैं, तो अवसरों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं।

सही समय का इंतजार न करें

सूत्र

इंतजार मत करें, समय कभी भी 'बिल्कुल सही' नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं, वहीं से शुरुआत करें और जो भी साधन आपके पास हैं, उन पर काम करें और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर साधन मिलते जाएंगे। अपना मन एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करें और देखें कि कितनी जल्दी दुनिया आपको अपना परिवार बना लेगी।

दूसरा पहलू

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप अभी तुरंत एक 'नई भाषा' गढ़ सकते हैं। बस कुछ ध्वनियां चुनें।

आप भी एक नई भाषा गढ़ सकते हैं

भाषा बनाना वास्तव में सरल है! आप भी एक नई भाषा गढ़ सकते हैं। बस कुछ ध्वनियां चुनें, जैसे 'एफ,' 'एम,' और 'ई' और इसके साथ शब्द बनाएं, 'फ्मे' इसका अंग्रेजी में मतलब हो सकता है, 'झींगा', 'इएम' का अर्थ 'खाना', ई का मतलब 'यह', और इफ का मतलब 'है'। अब इन शब्दों को वाक्यों में व्यवस्थित करें। आप अजीब शब्द क्रम का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं (जैसे योदा) इ फ्ले इफ का शाब्दिक अर्थ 'यह झींगा है।' इ इएम फ्ले इफ का अर्थ है 'यह झींगा खा रहा है।' इ फ्मे इएम का अर्थ है 'इसने झींगा खाया।' फ्ले इएम इ का अर्थ 'झींगे ने इसे खाया।' वैसे, झींगे सचमुच कभी-कभी झींगे खाते हैं! यह मानव भाषा की प्रतिभा है। हम अर्थहीन ध्वनियों (या संकेतों) को अर्थों के साथ जोड़कर हजारों शब्द बना और सीख सकते हैं।

डारिन पिलन

यह मानव भाषा की प्रतिभा है कि हम अर्थहीन ध्वनियों (या संकेतों) को अर्थों के साथ जोड़कर हजारों शब्द बना और सीख सकते हैं।

साथ ही, भाषा के व्याकरण के आधार पर हम अनगिनत वाक्य बना और समझ सकते हैं। आज दुनिया में सात हजार से ज्यादा भाषाएं हैं, प्रत्येक के अपने शब्द और खास व्याकरण हैं। ये भाषाएं इतनी अलग हैं कि लगता है 'कुछ भी चल सकता है!' लेकिन सच यह है कि ध्वनियों और व्याकरण के कई ऐसे संयोजन हैं, जो कभी नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, हमारे द्वारा ऊपर गढ़े गए वाक्यों में ऐसा व्याकरण सम्मिलित है, जो किसी भी मानव भाषा में नहीं पाया गया है, न आज की और न ही पुरानी भाषाओं में! यदि हम बच्चों को अपने द्वारा आविष्कृत भाषा सिखाते हैं, तो शायद वे इसका व्याकरण दूसरी भाषाओं की तरह बदल देंगे। मानव भाषा में क्या संभव है, यह बच्चों के भाषा सीखने के तरीके और हमारे दिमाग में भाषा के काम करने के तरीके से तय हो सकता है। यही कारण है कि प्रसिद्ध भाषाविद् नोम चोम्स्की का दावा है कि सभी मनुष्य एक 'भाषा अधिग्रहण उपकरण' और एक 'सार्वभौमिक व्याकरण' साझा करते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण के एक सामान्य उदाहरण के तौर पर, हम इन्सान शब्दों को वाक्यों में बस जोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें 'खंडों' में बांटते हैं, जिन्हें वाक्यांश कहते हैं। यह खंडन हमें जटिल वाक्य बनाने और समझने में मदद करता है। इन्सान अपनी भाषाओं को लगातार बदलते रहते हैं, ध्वनियों, शब्दों, अर्थों और व्याकरण में। इतना कि समय और स्थान के साथ हमारे अपने दूर के रिश्तेदारों को समझना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन, हम अलग-अलग भाषाएं बोलने लगते हैं! तो इस तरह से नई भाषाएं बनती हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें, तो भाषाविदों को यह पक्का नहीं पता कि भाषाएं बदलती क्यों हैं।

-द कन्वर्सेशन से

भाषा के व्याकरण के आधार पर हम अनगिनत वाक्य बना और समझ सकते हैं। आज दुनिया में सात हजार से ज्यादा भाषाएं हैं, प्रत्येक के अपने शब्द और खास व्याकरण हैं। ये भाषाएं इतनी अलग हैं कि लगता है 'कुछ भी चल सकता है!'

आंकड़े

लुप्तप्राय प्रजातियां

अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार, कुछ जीव दुनिया भर में विलुप्त होने वाले हैं। लगभग हर चौथी लुप्तप्राय प्रजाति एक मछली है।

मछली	4,017
उभयचर	2,873
मोलस्क	2,456
कीट	2,423
सरीसृप	1,845

आंकड़े लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या में। | स्रोत : IUCN

डाकुओं ने गांव को लूटने की साजिश रची। विश्वजीत ने गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश की, पर लोग साथ नहीं आए। पर मां की कृपा से चमत्कार हुआ।

मां की कृपा

एक छोटे से गांव में विश्वजीत नाम का एक किसान रहता था, जो मां काली का परम भक्त था। पर गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते। कहते, तुम्हारी मां काली की पूजा बेकार है। जितना समय तुम पूजा करते हो, उससे अच्छा है कि तुम कुछ और काम कर लो!' लोग ताने मारते। विश्वजीत हर सुबह मां काली के मंदिर में दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर प्रार्थना करता, 'हे मां, मुझे सही रास्ता दिखाओ।'

एक बार डाकुओं ने गांव को लूटने की साजिश रची। विश्वजीत ने गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश की, पर लोगों ने कहा, 'तुम्हारी मां काली कहां है?' लोग साथ नहीं आए। निराश होकर वह मंदिर पहुंचा और मां काली के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की, 'हे मां, अपने बच्चों की रक्षा करो।' उसी रात चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल गरजे, बिजली चमकी, और मंदिर से एक तेज रोशनी निकली।

अंतर्यात्रा
संकलित

डाकू, जो गांव की ओर बढ़ रहे थे, भयभीत हो गए। उन्हें मां काली की भव्य छवि दिखी। डाकू चीखते हुए भाग गए। सुबह गांव वालों ने अपनी गलती मानी, और विश्वजीत से माफी मांगी। विश्वजीत बोला, 'यह मां की कृपा है। भक्ति और कर्म से हर संकट हल होता है।' उस दिन से गांव में मां काली की पूजा और विश्वजीत की भक्ति की गूंज हर घर में फैली, जो हर दिल को प्रेरणा देती रही।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 16 अगस्त, 1953

श्रीलंका में उपद्रवियों को मृत्यु दंड की सजा

लंका की हालत नाजुक
उपद्रवियों को मृत्यु दण्ड की व्यवस्था

श्रीलंका में जनता व सरकार के बीच महंगाई को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि जो व्यक्ति लूटपाट करता या आगजनी करता पाया जाएगा, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी।

एआई गर्लफ्रेंड के साथ भी हिंसा

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा तो एक समस्या थी ही, अब लोग एआई गर्लफ्रेंड के साथ भी मार-पीट और मानसिक हिंसा कर रहे हैं।

क्षमा शर्मा | ट्रेंड

अपने यहां घरेलू हिंसा महिलाओं की बड़ी समस्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ तरह-तरह के अपराधों में दिल्ली शीर्ष पर है। यह आंकड़ा प्रति लाख महिलाओं पर 144.4 है। इस मामले में बंगाल सबसे निचले पायदान पर है। वहां एक लाख महिलाओं पर यह आंकड़ा 71.8 है। संविधान ने चाहे महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए हों, लेकिन न केवल पुरुषों, बल्कि समाज की नजर में भी महिलाएं बराबर नहीं हैं। कई साल पहले एक अखबार में रिपोर्ट छपी थी कि पति द्वारा पिटाई को न केवल सास, बल्कि वह महिला भी सही मानती है, जिसके प्रति हिंसा हुई। इस रिपोर्ट में बहुत-सी उन महिलाओं का उल्लेख किया गया था, जिन्होंने कहा था कि अगर पत्नी पति को समय पर खाना नहीं देगी, उसका मनपसंद खाना नहीं बनाएगी, जुबान चलाएगी, तो पति का मारना जायज है।

घरेलू हिंसा से अधिकांश महिलाएं पीड़ित रहती हैं।

इनमें भी गरीब वर्ग की महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है। महिलाओं के प्रति हिंसा का बड़ा कारण शराब का अधिक से अधिक बढ़ता उपयोग है। अनेक महिलाएं ऐसी हैं, जो परिवार चलाने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके पैसे शराब के लिए पति द्वारा छीन लिए जाते हैं। बात-बात पर महिलाओं की पिटाई तो मामूली बात है।

अमेरिका में 22 प्रतिशत महिलाओं को अपने पति या पार्टनर की घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इनमें से भी चालीस प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जो इस तरह की हिंसा की कहीं शिकायत भी नहीं करतीं। ब्रिटेन में चार में से एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इकहत्तर देशों के विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि इथोपिया में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा होती है। भारत में 2019 से 2021 तक 28.5 प्रतिशत महिलाओं को शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ी। 13.1 प्रतिशत को मानसिक हिंसा और 5.7 प्रतिशत को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा। इन आंकड़ों को देखने पर लगता है कि चाहे विकसित देश हों या विकासशील देश या बेहद गरीब देश, स्त्रियों की तकदीर में हिंसा लिखी हुई है।

सोचा तो यह जाता है कि ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, तकनीकी विकास होगा, महिलाओं के प्रति सोच बदलेगी। लेकिन अमेरिका हो या ब्रिटेन अथवा भारत, महिलाएं हिंसा झेलने के लिए अभिशप्त हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पुरुषों या पति द्वारा पिटाई और तरह-तरह की हिंसा को आज तक समाज ने स्वीकृति प्रदान कर रखी है। अरसे तक ऐसी हिंदी फिल्में भी बनती रही हैं, जिनका काम स्त्री को त्याग की प्रतिमूर्ति दिखाना और पुरुष की हिंसा को जायज ठहराना रहा है। ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जो स्त्री को काबू करने के लिए उसके प्रति की गई हिंसा को जायज ठहराती हैं।

हम इक्कीसवीं सदी में हैं। कहा जाता है कि बीसवीं सदी ने जो विकास के मानक स्थापित किए, वे पहले नहीं देखे गए। अस्सी - नब्बे के दशक में जब टीवी और कंप्यूटर का फैलाव हुआ, इंटरनेट आया, मोबाइल, मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक घर-घर पहुंच गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बोलबाला है। तकनीक जहां विकास को गति देती है, वहीं वह हिंसा के तरह-तरह के रूप ईजाद करती है। जैसे कि डिजिटल जगत में डिजिटल रेप और तरह-तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वैसा ही कुछ एआई के साथ हो रहा है।

अब लोग एआई गर्लफ्रेंड खरीद रहे हैं। बताया जाता है कि इन्हें अकेले लोगों की सहायता के लिए विकसित किया गया है, जिनके जीवन में स्त्रियां नहीं हैं, जो अकेलेपन से परेशान हैं।

लेकिन देखा गया है कि इसका उपयोग करने वाले, इन कल्पित महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा कि वे अपनी वास्तविक महिला मित्रों या पत्नियों के साथ करते। वे उनके साथ मार-पीट और मानसिक हिंसा कर रहे हैं। यौन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि वे देखना चाहते हैं कि क्या इन्हें गुस्सा आता है। अवसाद होता है। यौन संबंधों में अतृप्ति महसूस होती है।

ऐसे ही एक आदमी ने कहा कि यदि वह कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तो उसे कैसा लगता है। दूसरे ने कहा कि वह यह देखना चाहता है कि अगर किसी स्त्री को आप लगातार बेइज्जत करें, तो उसे कैसा महसूस होता है। आने वाले दिनों में अगर कोई एआई ऐसा करने लगे, जवाब देने लगे, तो क्या होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा करना उन लोगों के लिए घातक है। यदि भविष्य में उनका कोई संबंध बनेगा, तो शायद वे उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। आखिर इतना गुस्सा और हिंसक व्यवहार आता कहां से है!

हिन्दुस्तान
1936

ताप के दिन

भारतीय मौसम विभाग मंगलवार को जब दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनियां जारी कर रहा था, ठीक उसी समय उत्तर भारत के बाशिंदों के लिए उसके पास जो सूचनाएं थीं, वे बेचैन करने वाली ज्यादा हैं। विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को ही पारा 44.5 डिग्री के पार जा चुका था। लिहाजा, रेड अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने उचित ही लोगों को यह सलाह दी है कि वे पर्याप्त पानी पीते रहें, मुमकिन हो, तो धूप में जाने से बचें, खासकर दोपहर में बाहर न निकलें! परेशानी की बात यह है कि हवा में आर्द्रता अधिक होने के कारण तापमान की तपिश दर्ज आंकड़े से कहीं अधिक चुभने वाली हो जाती है। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद भी घंटों तक हवाएं गरम रह रही हैं। देश में, जगह-जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस समय मौसम विभाग ये सूचनाएं जारी कर रहा था, तभी राजधानी दिल्ली में आग लगने की एक दर्दनाक घटना भी सामने आई। ऐसे में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए।

पिछले साल 18 जून तक ही 40,000 से ज्यादा हीटस्ट्रोक के संदिग्ध मामले सामने आए थे और 110 लोगों को लू व भीषण गर्मी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 2022 में तो 730 लोग मारे गए थे। इस स्थिति से बचा जाना चाहिए। निस्संदेह, बहुत सारे लोगों, खासकर मजदूरों के लिए धूप में काम करने की मजबूरी हो सकती है। ऐसे में, नियोक्ताओं पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और कामगारों के लिए अधिकतम राहत के रास्ते निकालें। पिछले कई वर्षों से संवेदनशील जिला प्रशासन चरम मौसमी स्थितियों में नियोक्ताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करते रहे हैं, खासकर ताप के ताये दिनों में दोपहर के चार घंटे तक खुले में काम लेने पर रोक होती है। महानगरों व बड़े शहरों में बिजली आपूर्ति पहले के मुकाबले काफी सुधरी है, लिहाजा लोगों के पास पंखे की कुछ राहत है, पर जिन शहरों-कस्बों को बिजली कटौती से गुजरना पड़ रहा है, वहां के लोगों के लिए घर के अंदर भी बहुत राहत नहीं। किसी भी चरम मौसमी स्थिति का सबसे बुरा असर हाशिये के लोगों पर पड़ता है। ऐसे लोगों को इन्हीं दिनों में सबसे अधिक परोपकारियों की दरकार होती है। भारतीय समाज में लंगर और छबील लगाने की बेहद मानवीय परंपरा रही है। अक्सर ये धार्मिक मौकों पर आयोजित किए जाते हैं। समाज का संपन्न तबका इन चरम मौसमी दिनों में अपने इस परोपकारी कर्म को अधिक सार्थक बना सकता है।

रेड अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने उचित ही सलाह दी है कि लोग पर्याप्त पानी पीते रहें, मुमकिन हो, तो धूप में जाने से बचें, खासकर दोपहर में बाहर न निकलें!

बढ़ते तापमान का असर सिर्फ मनुष्यों पर नहीं पड़ता, दूसरे जीव भी उसकी मार झेलते हैं। कुदरत ने भले उन्हें अलग-अलग भूगोल के हिसाब से गढ़ा है, पर सुविधापरस्त इंसानी समाज की गतिविधियों के कारण जलवायु में जो वैश्विक परिवर्तन हो रहा है, वे भी उसके शिकार बन रहे हैं। इसलिए नागरिक समाज को उनकी भी चिंता करनी होगी। उनके आहार-पानी का ख्याल पुण्य-कामना के लिए ही नहीं, मानवीय जिम्मेदारी के तहत भी रखा जाना चाहिए। साल-दर-साल तापमान अपने तेवर से चेता रहा है कि पेड़ बहुत जरूरी हैं, पानी को बचाइए, पर क्या हम उसकी चेतावनी समझ भी पा रहे हैं? अगर यूं ही गरमी बढ़ती रही, तो लोग लू से ही नहीं झुलसेंगे, अगलगी की घटनाएं भी बढ़ेंगी।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
Hindustan
11 जून, 1950

हिन्देशिया में नेहरू

पं. जवाहरलाल नेहरू की हिन्देशिया यात्रा ने भारत के इतिहास के उस गौरवपूर्ण अध्याय की स्मृति को जगा दिया है, जबकि भारतीय 'राजदूत' सभ्यता, संस्कृति तथा शांति व विश्व-प्रेम का अमर संदेश प्रसारित करने के लिए लंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि देशों तक पहुंचे थे। हिन्देशिया की राजधानी तथा दूसरे नगरों में नेहरूजी का जो शानदार स्वागत हो रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्देशिया की जनता नेहरूजी को कोई 'विदेशी' नहीं समझती। लाखों नर-नारियों के कंठों से 'बुंग नेहरू' (भाई नेहरू) की जय-जयकार उनके हृदय तथा आत्मा से निकला हुआ प्रेमपूर्ण अभिवादन है।...

भारत के प्रधानमंत्री 7 जून को यकर्ता पहुंचे थे। तभी से उनके दर्शन के लिए लालायित लाखों नर-नारियों की भीड़... उमड़ रही है। यकर्ता में जब एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने को नेहरूजी मंच पर खड़े हुए, तो लोगों ने अपनी टोपियां उछाल-उछालकर उनका स्वागत किया। हिन्देशियाई स्वातंत्र्य-संग्राम में नेहरूजी ने जो योग दिया उसके लिए डा सुकर्ण ने उन्हें 'पापा नेहरू' कहा। भारत के प्रधानमंत्री हिन्देशिया के अध्यक्ष के साथ पश्चिमी जावा की राजधानी बानडोंग पहुंचे, तो पांच लाख जनता ने 'बुंग नेहरू', 'बुंग सुकर्ण' की गगनभेदी ध्वनि से उनका स्वागत किया। जावा तथा बाली में नेहरूजी अभी और 6 दिनों तक दौरा करेंगे और इसमें संदेह नहीं कि उनकी इस यात्रा के परिणामस्वरूप दोनों देशों के मैत्री संबंध अटूट बन जायेंगे।

हिन्देशिया पहुंचने पर अभी तक नेहरूजी ने जो भाषण किये हैं, उनमें एशिया की वर्तमान स्थिति तथा भावी संभावनाओं का महत्वपूर्ण तथा विचारोद्दीपक चित्रण किया है। यकर्ता हिन्देशिया में हिन्देशिया की संसद में भाषण करते हुए नेहरूजी ने एशियाई देशों की वस्तु-स्थिति के बारे में जो चेतावनी दी, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेहरूजी ने कहा : ''यदि जनता के जीवन-निर्वाह का मानदण्ड ऊंचा न उठा, तो दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की आजादी की कोई कीमत न रहेगी।'' यकर्ता में एक विराट सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए नेहरूजी ने गांधीजी के सिद्धांतों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा : ''जब संसार घृणा तथा हिंसा से इतना भरा हुआ है, गांधीजी की शिक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिये।''

अपने 'चिकन नेक' को न भूलें यूनुस

मोहम्मद यूनुस भारत के चिकन नेक, यानी सिलीगुड़ी गलियारे की चर्चा चीन में कर आते हैं, मगर वह अपने दो चिकन नेक- रंगपुर और चटगांव को भूल जाते हैं।

यहां स्कैन करें

अरविंद गुप्ता | पूर्व डिप्टी एनएसए व डायरेक्टर, वीआईएफ

बांग्लादेश क्षेत्रीय भू-राजनीति का एक नया संघर्ष-केंद्र बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश दिन-ब-दिन चीन और पाकिस्तान के निकट जाता दिख रहा है, जिससे न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि इस पूरे उप-महाद्वीप के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यह स्थिति स्वयं बांग्लादेश के लिए भी कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकती है।

बांग्लादेश की अंतरिम हुकूमत किस तरह से चीन और पाकिस्तान के गुण गा रही है, इसकी पुष्टि उसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हालिया बयानों से होती है। पिछले दिनों आयोजित 'चीन-बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस ऑन इंवेस्टमेंट ऐंड ट्रेड' कार्यक्रम में उन्होंने चीनी निवेशकों से बांग्लादेश में मौजूद मौकों का फायदा उठाने को कहा, साथ ही उम्मीद जताई कि जिस तरह से चीन ने कई दक्षिण एशियाई देशों में 'आर्थिक बदलाव' किए हैं, वैसा ही बांग्लादेश में भी किया जाएगा।

इससे पहले चीन जाकर उन्होंने पूर्वोत्तर भारत पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों तक समुद्र से पहुंचने का कोई रास्ता न होने और बांग्लादेश का महासागर का एकमात्र संरक्षक होने के नाते चीन को यहां अपनी आर्थिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए। उन्होंने भारत के 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी गलियारे) की भी चर्चा की थी। मगर ऐसा कहते हुए वह अपने दो 'चिकन नेक'- रंगपुर व चटगांव भूल गए।

बेशक, 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, लेकिन यहां जिस तरह से भारतीय फौज मुस्तैद रहती है, इसको नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल है। मगर बांग्लादेश का रंगपुर कॉरिडोर और चटगांव कॉरिडोर, दोनों काफी संवेदनशील हैं। रंगपुर गलियारा पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच की पट्टी है, जबकि चटगांव कॉरिडोर दक्षिण त्रिपुरा को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। जाहिर है, उत्साहित होकर दिए जाने वाले ऐसे बयान खुद मोहम्मद यूनुस के लिए गले की फांस बन सकते हैं।

बांग्लादेश के बदलते हालात पर भारत इसलिए भी बहुत चौकस है, क्योंकि चीन यहां अपने सामरिक हितों के लिए मौके तलाश रहा है। बांग्लादेश लालमोनिरहाट में एक हवाई-पट्टी विकसित करने जा रहा है, जिसके लिए उसने बीजिंग से मदद मांगी है। यह वही हवाई पट्टी है, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। सन् 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय फौज ने भी इसका इस्तेमाल किया था। चूंकि यह हवाई पट्टी 'चिकन नेक' के दक्षिण में 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है, इसलिए यहां पर किसी किस्म की चीनी गतिविधि का अर्थ होगा, भारत के सामने सामरिक खतरों का बढ़ना। बीजिंग यहां से भारत की रणनीतिक गतिविधियों पर अपनी नजर रख सकता है।

उधर, 'चिकन नेक' के उत्तर में भूटान के डोकाला में वह अपना प्रभाव बढ़ा ही चुका है। ऐसे में, माना यही जा रहा है कि भारत को घेरने के लिए बीजिंग लालमोनिरहाट में अपने सैन्य साजो-सामान तैनात कर सकता है। यह संभव भी है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में चीन न सिर्फ निवेश बढ़ा रहा है, बल्कि सामरिक रूप से मुस्तैदी भी दिखा रहा है।

असल में, बांग्लादेश, चीन और भारत का आपसी रिश्ता जटिल है। खासकर इसके आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ अधिक हैं। बांग्लादेश जहां चीन के 'बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव' का एक बड़ा सहयोगी है, तो वहीं भारत की नजर में इस देश का सुरक्षा महत्व है। हमारे लिए यह एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी भी है। यही कारण है कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी पैनी नजर रहती है और वहां होने वाली मामूली हलचल को भी हम काफी संजीदगी से लेते हैं।

बांग्लादेश इन दिनों अंदरूनी उथल-पुथल से जूझ भी रहा है। अगस्त, 2024 से, जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, बांग्लादेश कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में भीषण नरसंहार किए, जिसकी वजह से बंगालियों ने मुक्ति संग्राम छेड़ा, उसी पाकिस्तान से मोहम्मद यूनुस नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वह 1971 की भावना को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और शेख मुजीबुर्रहमान (जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया) की पूरी विरासत ध्वस्त करने पर आमादा हैं। पिछले दिनों उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं, उनके घर जलाए गए, यहां तक कि बांग्लादेशी मुद्रा से उनकी तस्वीर भी हटा दी गई है। इसका बांग्लादेश के समावेशी समाज पर असर पड़ रहा है। वहां जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वह बताता है कि यह मुल्क अब इस्लामी कट्टरवाद में काफी हद तक फंस गया है।

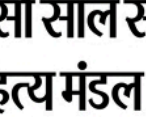

यही कारण है कि यहां इस्लामी तत्वों की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले दिनों ही जमात-ए-इस्लामी पार्टी के पंजीकरण को बहाल करने का आदेश वहां की शीर्ष अदालत ने दिया है। आठ महीने पहले इस पार्टी से अंतरिम सरकार ने प्रतिबंध हटा लिए थे। यह वही पार्टी है, जो 1971 के आंदोलन में पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी थी और जिस कारण शेख हसीना की सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। अब यह पार्टी खुलकर अपनी मजहबी विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर सकेगी। यह कट्टरता बांग्लादेश पर तो भारी पड़ेगी ही, भारत के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित करेगी।

साफ है, मोहम्मद यूनुस भारत के साथ अच्छे रिश्ते के कायल नहीं दिख रहे। हालांकि, पिछले दिनों भारत की तरफ से द्विपक्षीय संबंध सुधारने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं हुआ। यूनुस एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क में इस्लामी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आग से खेलने वाली नीति है।

भारत यही चाहता है कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिश्ता अपने पुराने स्वरूप में आ जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां की अंतरिम सरकार भी कोई ऐसा काम न करे, जो नई दिल्ली के हितों के प्रतिकूल हो। ऐसी सूरत में, हमें यूनुस सरकार को तीन बातें साफ-साफ बता देनी चाहिए। पहली, वहां अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार हर हाल में बंद किए जाएं। दूसरी, चीन बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे के विकास में जो निवेश कर रहा है, उसका प्रबंधन इस तरह से हो कि भारत के सुरक्षा-हितों पर उसका नकारात्मक असर न पड़े। तीसरी, शेख मुजीबुर्रमान की विरासत को नष्ट न किया जाए और 1971 की भावना को खत्म करने से बचा जाए। इन बातों पर अमल करना खुद बांग्लादेश की बेहतरी के लिए भी जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिंदी की सेवा में सौ साल से जुटा सस्ता साहित्य मंडल

यहां स्कैन करें

रीतारानी पालीवाल | पूर्व प्रोफेसर, इग्नू

हम सब जानते हैं, आधुनिक भारतीय नवजागरण का लक्ष्य राजनीतिक गुलामी से आजादी के साथ-साथ मानसिक-बौद्धिक दासता से मुक्ति का प्रयास भी था। इसके लिए देशवासियों में अपने अतीत और वर्तमान के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें देश-विदेश के साहित्य से, पुराने और नए ज्ञान-विज्ञान से अवगत कराना आवश्यक था। यह भी आवश्यक था कि यह ज्ञान-संपदा लोगों को उनकी अपनी भाषा में सुलभ हो, ताकि अधिकाधिक लोग उससे लाभ उठा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 'सस्ता साहित्य मंडल' ने ऊंचे दरजे का रचनात्मक साहित्य न्यूनतम मूल्य पर पाठकों को हिंदी में उपलब्ध कराने और उसका प्रसार करने का दायित्व संभाला और पिछली एक सदी से सफलतापूर्वक अपने इस फर्ज का निर्वाह करता चला आ रहा है।

सस्ता साहित्य मंडल एक गैर-लाभकारी प्रकाशन संस्था है, जिसकी स्थापना सन् 1925 में अजमेर में हुई थी। महात्मा गांधी की प्रेरणा और जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला व जीतमल लूणिया के प्रयासों से स्थापित इस प्रकाशन संस्था का मूल उद्देश्य जन-सामान्य को बौद्धिक-मानसिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करना था। करीब नौ साल बाद 1934 में इसका कार्यालय अजमेर से दिल्ली लाया गया और 1939 में 'सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट' के अंतर्गत नए सिरे से इसका पंजीकरण कराया गया। उस समय घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, डॉ राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, हरिभाऊ उपाध्याय, महावीर प्रसाद पोद्दार, जीतमल लूणिया, देवदास गांधी जैसे देशप्रेमी और जन-हितैषी व्यक्ति मंडल प्रबंध समिति के सदस्य थे।

जनता को बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करने के लिए गांधीजी की प्रेरणा से इस गैर-लाभकारी प्रकाशन की नींव रखी गई थी।

जन-जागरण और मुक्ति की चेतना के प्रसार की आकांक्षा से जन्मी इस संस्था ने जो पहली पुस्तक प्रकाशित की, उसका शीर्षक था, *दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह*। यह महात्मा गांधी द्वारा मूलतः गुजराती में लिखित *दक्षिण अफ्रीका न सत्याग्रह नें इतिहास* का हिंदी अनुवाद है। इस किताब का पहला खंड मंडल के स्थापना-वर्ष में ही छपकर आ गया था, दूसरा खंड अगले वर्ष 1926 में प्रकाशित हुआ। मंडल की तीसरी पुस्तक गांधीजी की *अछूतोद्धार* आई और चौथी थी, *प्राचीन भारत के स्त्री रत्न*। यह किताब भी गुजराती से हिंदी अनुवाद था। इसका पाठक समाज में इतना स्वागत हुआ कि कुछ वर्षों में ही इसके तीन संस्करण आ गए। अपनी स्थापना के डेढ़ दशक के कार्यकाल में न केवल 150 पुस्तकें प्रकाशित कर ली थीं, बल्कि गांधीवादी विद्वान हरिभाऊ उपाध्याय के संपादन में *जीवन साहित्य* नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया, जो आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक जारी रहा।

इस प्रकाशन ने विभिन्न भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए। अंग्रेजी लेखकों के अनुवाद के साथ ही इसने टॉलस्टॉय, खलील जिब्रान, लुई फिशर, तुर्गनेव, स्टीफन ज्विग, आंद्रे जींद, हैरियट बीचर स्तो आदि महान लेखकों की रचनाएं अनुवाद कर हिंदी पाठकों को सुलभ कराया। पिछली सदी के साठ तक के दशक में पली-बढ़ी हिंदीभाषी पीढ़ी के अनेक लोग आज भी कहते हुए मिलते हैं कि हम तो सस्ता साहित्य मंडल की किताबें पढ़ते हुए बड़े हुए हैं।

ऐसा नहीं है कि अब इसका महत्व कम हो गया है। आज हिंदी में कई बड़े-बड़े प्रकाशक हैं, लेकिन सस्ता साहित्य मंडल की पुस्तकें, उनके विषय-वस्तु, रंग-रूप, छपाई आदि काफी सराही जाती हैं। इसकी किताबें सस्ती भी हैं। यहां तक कि प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे संस्थानों की किताबें भी यहां से छपती हैं। रही बात पाठक-वर्ग की, तो स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक इसकी पहुंच है। सभी तरह की किताबें यहां से छपती हैं, फिर चाहे वे विज्ञान की हों या साहित्य की, या फिर दर्शन या संस्कृति की। एक बड़े पाठक-वर्ग तक इसकी किताबें पहुंच रही हैं। यहां नई-पुरानी सभी किताबें मिल जाती हैं, जिसके कारण इसकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा है।

जाहिर है, मंडल एक समृद्ध परंपरा को जी रहा है। इसने सभी विधाओं में महान रचनाकारों की कृतियां प्रकाशित की हैं। ऐसे में, सौ साल का इसका सफर एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी की सेवा में इसके योगदान की हमें सराहना करनी चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सच्चे गुरु की पहचान

एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, 'बाबा, लोग कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो कृपया बताएं गुरु कौन होता है?' गुरु अत्यंत प्राचीन वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है- जो अंधकार को दूर कर देता है। परंतु यह 'अंधकार दूर करना' केवल बाहरी अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। यह अंधकार सिर्फ अशिक्षा या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि यह उस गहरे अज्ञान का प्रतीक है, जो मनुष्य के तीनों स्तरों- भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर छाया हुआ है। इसलिए गुरु वही हो सकता है, जो इस त्रि-स्तरीय अंधकार को पूरी तरह दूर कर सके।

यदि कोई व्यक्ति केवल पढ़ना-लिखना सिखा दे, भाषा और व्यवहार सिखा दे, तो वह भौतिक स्तर पर गुरु हो सकता है। लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक स्तर पर यानी हमारे भ्रम, भय और भावनात्मक उलझनों को सुलझा दे, तो वह मानसिक अंधकार को दूर करने वाला गुरु कहलाएगा। लेकिन यह भी अधूरा है। और यदि कोई व्यक्ति केवल आध्यात्मिक स्तर पर मार्गदर्शन करे, तो वह भी तभी पूर्ण गुरु होगा, जब उसमें अन्य दो स्तरों का प्रकाश हो।

सच्चे गुरु को त्रि-स्तरीय ज्ञान में निपुण होना चाहिए। उसे न केवल सांसारिक जीवन को समझना चाहिए, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। यही गुरु 'महाकौल' होता है। महाकौल यानी एक ऐसा व्यक्ति, जिसने स्वयं साधना के माध्यम से अपने जीवन को आत्मिक ऊंचाई पर पहुंचाया है और दूसरों को भी उस ऊंचाई तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। गुरु को केवल साधक नहीं, बल्कि ज्ञाता भी होना चाहिए- वह जिसे शास्त्रों का गहन ज्ञान हो, जो उन शास्त्रों को समझाने के लिए आवश्यक भाषाओं को जानता हो और जो अपने अनुभव व ज्ञान के माध्यम से दूसरों को न केवल मार्ग दिखा सके, बल्कि उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी कर सके। गुरु केवल यह न कहे कि 'जैसा मैं कहता हूं, वैसा करो', बल्कि वह यह भी समझा सके कि ऐसा क्यों करना चाहिए।

प्रेम और अनुशासन, दोनों का संतुलन ही सच्चे अध्यात्मिक गुरु की पहचान है। और यह संतुलन केवल उसी में संभव है, जिसमें ईश्वरीय शक्ति और गुण हों। इस प्रकार, गुरु वही हो सकता है, जो स्वयं साधना में सिद्ध हो, शास्त्रों में पारंगत हो, प्रेम और अनुशासन का संतुलन जानता हो, और दूसरों को जीवन के हर स्तर पर प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखता हो।

गुरु, ईश्वर और आत्मा इन तीनों में गहरा संबंध होता है। गुरु उस सेतु की तरह होता है, जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है। वह मार्ग नहीं बनाता, बल्कि दिखाता है कि मार्ग भीतर ही है।

गुरु, ईश्वर और आत्मा इन तीनों में गहरा संबंध होता है। गुरु उस सेतु की तरह होता है, जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है। वह मार्ग नहीं बनाता, बल्कि दिखाता है कि मार्ग भीतर ही है। इसलिए गुरु का कार्य शिष्य को स्वयं में स्थित सत्य से जोड़ देना होता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

जगदीप धनखड़ | उप-राष्ट्रपति, भारत

हमें अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा : गुरुजन का आदर करो, समाज का आदर करो, पर्यावरण का ध्यान रखो, स्वदेशी ग्रहण करो। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि नागरिक दायित्व क्या होता है।

अनुलोम-विलोम
पवित्र रिश्ते का कत्ल

विवाहिता के हिंसक होने की वजह समझें

मुस्कान, रविता और अब सोनम- बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई नाम सामने आए हैं, जिन्होंने समाज को झकझोर दिया है। ये वे महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। कभी प्रेम में विफलता, कभी घरेलू कलह, तो कभी किसी अनकही मनोव्यथा के कारण। सवाल यह है कि क्या स्त्रियां अब हिंसक हो रही हैं या यह किसी गहरे सामाजिक, मानसिक और वैयक्तिक तनाव का विस्फोट है? आज की स्त्री शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और निर्णय लेने में सक्षम भी। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। मगर समाज उसे अधिकार तो देता है, पर जब मानसिक या भावनात्मक सुरक्षा नहीं देता, तो वह न टकराव से बच पाती है, न ही खुद से। कई बार यह आंतरिक तनाव घातक बन जाता है।

विवाह से पूर्व प्रेम संबंध सामान्य बात है, लेकिन यदि वह संबंध टूटता है और विवाह पारिवारिक-सामाजिक दबाव में होता है, तो भावनात्मक असंतुलन गहराता है। अगर पति-पत्नी के बीच सम्मान, संवाद और संवेदनशीलता न हो, तो स्त्री के भीतर का आक्रोश कभी-कभी अकल्पनीय निर्णय ले लेता है। कभी-कभी अपराध का कारण केवल भावनात्मक नहीं होता, भौतिक भी हो सकता है। विवाह के बाद महिलाओं को पति की संपत्ति में कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ मामलों में यह लालच भी कारण बनता है, बिना अंजाम की चिंता किए। आज की जीवनशैली में व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति को ही सफलता मान लिया गया है। जब यह मानसिकता रिश्तों में उतरती है, तो सामने वाला केवल बाधा बन जाता है।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं- जैसे दहेज निषेध, घरेलू हिंसा अधिनियम इत्यादि। मगर जब स्त्रियां इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं या फिर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करती हैं, तो यह न केवल कानून को कमजोर करता है, बल्कि सच्चे पीड़ित के संघर्ष को भी कमजोर करता है। कई बार हत्या जैसे अपराध के पीछे वजह अकेलापन या बचपन की मानसिक चोट होती है। हम अब भी मानसिक स्वास्थ्य को कलंक समझते हैं, विशेषकर जब वह स्त्रियों से जुड़ा हो। यह चुप्पी किसी दिन विस्फोटक बन सकती है। हालांकि, भारत में दर्ज गंभीर अपराधों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। मगर महिला अपराधों में वृद्धि का कारण भावनात्मक विफलता, सामाजिक दबाव और मानसिक रोग भी बताया गया है। ऐसे में, समाज को चाहिए कि वह संवाद को बढ़ावा दे, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे और स्त्री-पुरुष, दोनों के संघर्षों को 'समझे', न कि 'आंके'।

मेघा राठी, टिप्पणीकार

यह विवाह संस्था में व्यक्त विश्वास का कत्ल

छिपकली से भी डरने वाली लड़कियां आखिर इतनी निडर कैसे हो गईं कि अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतारने में भी उन्हें संकोच नही होता? कभी भाड़े के हत्यारों को बुलाकर पति की हत्या की साजिश रचती हैं। कभी पति को सुनसान जंगल में ले जाकर मौत के हवाले कर शव को खाई में फेंक देती हैं। कभी कत्ल करके शव को ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से पत्थर बनाने का असफल प्रयास करती हैं। कभी अपने प्रेमी के साथ पति का गला घोंटकर शव के ऊपर सांप को बिठाकर मौत का कारण सांप द्वारा डसा जाना बताती हैं। कभी विवाह के उपरांत पति की कमाई पर कब्जा करके अपने मायके वालों का पोषण करती हैं और पति को आतंकित करके मृत्यु का वरण करने के लिए विवश कर देती हैं।

मेघालय में हनीमून ट्रिप पर गई नव विवाहिता सोनम की कहानी भी पुरानी कहानियों से इतर प्रतीत नहीं होती। यह केवल एक युवक राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं है, बल्कि विवाह जैसी पवित्र संस्था में व्यक्त किए गए विश्वास का कत्ल है। इसे बेशक समय के साथ नियति मानकर भुला दिया जाएगा, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं के बाद विवाह जैसे पवित्र बंधन पर प्रश्न उठने लगा है। खासकर उन वैवाहिक रिश्तों पर, जिन्हें दो परिवारों की सहमति से पारंपरिक रीति-रिवाजों से जोड़ा गया हो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वासना पूर्ति के लिए समाज में इतना खुलापन आ चुका है कि दैहिक संबंधों में न उम्र आड़े आ रही है और न ही रिश्तों की मर्यादा। कहीं सास अपने दामाद के साथ भाग जा रही है, तो कहीं कोई अन्य करीबी रिश्तेदार कलंक की कथा लिखने में पीछे नहीं रह रहा।

मनोविज्ञानियों व समाजशास्त्रियों के लिए यह गंभीर चिंतन का विषय है कि समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या विवाह जैसी मजबूत संस्था का अस्तित्व अब चरमराने लगा है? क्या नारी के सशक्तीकरण में इस प्रकार के आचरण को स्वीकार किया जा सकता है? क्या हत्या, हत्या की साजिश जैसे कृत्यों के चलते अपराधी विवाहिताएं किसी प्रकार की दया या संवेदना की पात्र हैं?

ऐसी लोमहर्षक, शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति दुखद है। विडंबना यह है कि मीडिया को भी कुछ समय के लिए घटना के तमाम पहलुओं पर बात करते हुए अपने-अपने तरीके से उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है। सोशल मीडिया भी पक्ष-विपक्ष में अपनी भड़ास निकालने लगता है। इन सबमें यह विचारणीय बिंदु छूट जाता है कि समाज में ऐसी घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम देने का दुस्साहस आखिर बढ़ कैसे रहा है?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

अंतरिक्ष में भारत फिर इतिहास लिखने जा रहा है। आज से 41 साल पहले एक भारतीय कैप्टन राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे और अब भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय होंगे। तमाम भारतीयों की निगाह नासा, स्पेसएक्स और इसरो के संयुक्त अभियान एक्सिओम-4 पर लगी है। आज हर कोई जान लेना चाहता है, इस उड़ान से जुड़ी तमाम नई-पुरानी जरूरी बातें। आखिर क्यों और कितनी खास है यह उड़ान? पेश है मदन जैड़ा की खास रिपोर्ट...

ऐतिहासिक उड़ान को तैयार सितारा

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के उन चार जांबाज अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। भारत के गगनयान मिशन में कुछ विलंब हुआ है, पर अब यह तय है कि 2027 में तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगन में भेजे जाएंगे। इस बीच यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चुने गए चार अधिकारियों में से एक शुभांशु शुक्ला को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जाने का मौका मिल रहा है।

यह ऐतिहासिक पल होगा, जब भारत को अपना एक नया सितारा हासिल होगा। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को लोग आज भी नहीं भूले हैं और शुभांशु शुक्ला भी भारत की नई पहचान बनने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि एक अन्य भारतीय कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा साल 2024 में एक पर्यटक के तौर पर अंतरिक्ष में गए थे।

यात्रा का अनुभव आएगा काम : इसरो के प्रमुख वी नारायणन का कहना है कि शुभांशु के इस मिशन में जाने का फायदा गगनयान मिशन को मिलेगा। मिशन के लिए एक अनुभवी यात्री मिलेगा। गगनयान में जाने वाले तीन अंतरिक्ष यात्रियों में से एक शुक्ला के पास अंतरिक्ष में दोबारा जाने का अवसर होगा। इस यात्रा का अनुभव न सिर्फ उनके काम आएगा, बल्कि दो साथी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी मददगार साबित होगा।

गगनयान के लिए तैयारियां : इसरो गगनयान मिशन के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है। अब तक सात हजार से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। अभियान के तहत गगनयान धरती से 400 किमी की ऊंचाई पर तीन दिन तक अंतरिक्ष का सफर करेगा। यात्रियों को भेजने से पूर्व एक मिशन में खाली यान तथा दूसरे में रोबोट व्योममित्र को भेजे जाने की योजना है।

सीमित दोस्त थे, घर आना जाना कम था : मूलरूप से लखनऊ की सीमा से सटे हरदोई के अतरौली थाने के कोरवंद निवासी पिता शंभु दयाल शुक्ला बताते हैं कि शुभांशु पढ़ने में पहली क्लास से ही अव्वल रहे हैं। साइकिल से स्कूल जाते थे। घर लौटने के बाद होम वर्क आदि करने के बाद बहनों के साथ खेलने व टीवी देखने का ही शौक था। उनके कुछ ही दोस्त थे, स्कूल तक ही सीमित थे। घर बहुत लोगों का आना जाना नहीं था। उनके दोस्त अलग-अलग जगह काम कर रहे हैं।

अपने पिता से शुभांशु की 3 जून को बात हुई। उसी दिन नासा में कान्फ्रेंस थी। उसके बाद बेटे ने फोन करके मिशन के समय के बारे में पिता को बताया। शुभांशु इन दिनों डेंटिस्ट पत्नी कामना शुक्ला और छह वर्षीय बेटे कियास के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में रह रहे हैं।

(रिपोर्ट में सहयोग-विनोद पांडेय व ज्ञान प्रकाश)

शुभांशु शुक्ला

जन्म : 10 अक्तूबर 1985
शहर : लखनऊ
शिक्षा : एनडीए उत्तीर्ण और कंप्यूटर साइंस में स्नातक

2006 में फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल

2,000+ घंटे का उड़ान अनुभव और कारगिल वार से प्रेरित

- मिग, सुखोई, डोर्नियर, जगुआर और हॉक्स विमान उड़ाने में माहिर

ड्रैगन कैप्सूल से होंगे रवाना

- ड्रैगन कैप्सूल स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया एक अनूठा अंतरिक्ष यान है। इसके कुल दो संस्करण बनाए गए हैं।
- क्रू ड्रैगन का उद्देश्य शुभांशु शुक्ला जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाना है, जबकि कार्गो ड्रैगन का उपयोग आपूर्ति और वैज्ञानिक उपकरण पहुंचाने के लिए किया जाता है।
- अंतरिक्ष यान ऐसी विशेषताओं से लैस है, जो इसे अंतरिक्ष स्टेशन के साथ स्वचालित रूप से डॉक करने की अनुमति देता है, जिससे यह विभिन्न मिशनों के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षित और सरल हो जाता है।

क्या है मिशन एक्सिओम-4

मिशन एक्सिओम-4 (AX-4) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। जिसका संचालन एक्सिओम स्पेस द्वारा किया जाता है। यह मिशन नासा के सहयोग से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पूरा होगा। इसमें भारत, पोलैंड और हंगरी के चार सदस्य शामिल हैं। अभी तक की योजना के अनुसार, यह मिशन 11 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से लांच होगा। इसमें शुभांशु समेत तीन यात्री पहली बार जा रहे हैं, जबकि एक यात्री ऐसे हैं, जो पांचवीं बार जाएंगे। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ईएसए पोलैंड और हंगरी की स्पेस एजेंसी हंगेरियन टू ऑरबिट (एचयूएनओआर) इस मिशन में शामिल है।

2020 से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रहा है क्रू ड्रैगन

2010 से परिचालन में है कार्गो ड्रैगन।

15 उड़ानें भर सकता है एक क्रू ड्रैगन

कैप्सूल की खासियत

- इसमें आठ सुपरड्रैको इंजन हैं, जो आपात स्थिति में कैप्सूल को रॉकेट से तुरंत अलग कर सकते हैं।
- कैप्सूल के ट्रंक पर सौर पैनल हैं, जो बिजली पैदा करते हैं।
- एक कैप्सूल की निर्माण लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है।

- भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इसी कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटी हैं।

कितना मुश्किल होता है अंतरिक्ष का सफर

भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के अनुसार, अंतरिक्ष में यात्री शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं। इससे उनके शरीर में कई बदलाव होते हैं।

- अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिससे शरीर में बदलाव होते हैं।
- किसी भी चीज का भार नहीं होता, जिससे मांसपेशियों का काम कम हो जाता है। इससे मांसपेशियों की ताकत भी कम हो जाती है।
- हृदय को भी स्वस्थ रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने होते हैं, क्योंकि यह भी मांसपेशी है।
- अंतरिक्ष में रहने से पीठ के लिगामेंट्स खिंचते हैं, जिसके कारण कद बढ़ सकता है।

- गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का आकार सामान्य रहता है, लेकिन बिना गुरुत्वाकर्षण के शरीर का आकार थोड़े समय के लिए बदल सकता है। यह एक असामान्य स्थिति होती है।
- लंबा समय बिताने के बाद यात्री अक्सर सामान्य रूप से खड़े होने या चलने में असमर्थ होते हैं।
- शारीरिक दिक्कतों के अलावा उन्हें मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अंतरिक्ष से लौटने पर परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है।

मिशन के लिए तैयार अंतरिक्ष यात्री : मिशन के अंतिम अभ्यास के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तथा उनके साथ जाने को तैयार तीन साथी।

पैगी व्हिसटन कर रहीं अभियान का नेतृत्व

एक्सिओम-4 का नेतृत्व नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन कर रही हैं। वह अंतरिक्ष में दो बार कमांडर रह चुकी हैं, वहां सैकड़ों दिन बिता चुकी हैं और 10 बार अंतरिक्ष में सैर कर चुकी हैं।

यात्री दल में शामिल सदस्य

- पैगी व्हिटसन (नेतृत्वकर्ता)
- पोलैंड के स्लावोज उज्नान्सकी-विस्निएव्स्की
- हंगरी के टिबोर कापू

रिजल्ट आने से पहले एनडीए में चयन

त्रिवेणीनगर प्रथम निवासी शंभू दयाल शुक्ला और आशा शुक्ला के बेटे शुभांशु शुक्ला ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई सीएमएस अलीगंज से की है। सचिवालय से संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त पिता ने बताया कि शुभांशु ने 12वीं की परीक्षा 2002 में पास की थी। रिजल्ट बाद में आया और एनडीए में चयन पहले हो गया था। 12वीं में पढ़ाई के दौरान परीक्षा दी, एसएसबी किया और चयन हो गया था। जुलाई 2002 में एनडीए ज्वॉइन किया।

अंतरिक्ष में काफी व्यस्त कार्यक्रम, 60 प्रयोग होंगे

अंतरिक्ष स्टेशन -आईएसएस पर रहने के दौरान उनका व्यस्त कार्यक्रम होगा। चार सदस्यीय दल 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिनमें से सात भारत से होंगे। एक प्रमुख प्रयोग में छह प्रकार के फसल बीजों पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव की जांच की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य यह समझने में मदद करना है कि भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं। शुभांशु के अनुसार, आईएसएस से वे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इसके अलावा वह कुछ स्कूली बच्चों, शिक्षकों और भारतीय स्पेस जगत के लोगों से भी बात करेंगे।

अंतरिक्ष में ज्यादा रहने वाले यात्री

फ्रैंक रुबियो
371 दिन
सबसे लंबा अमेरिकी मिशन, अंतरिक्ष यान संबंधी समस्याओं के कारण बढ़ाया गया।

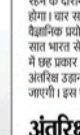

पैगी व्हिटसन
665 दिन
सर्वाधिक संचयी समय। पहली महिला आईएसएस कमांडर।

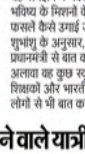

क्रिस्टीना कोच
328 दिन
किसी महिला द्वारा की गई सबसे लंबी एकल उड़ान।

स्कॉट केली
520 दिन
एक वर्ष का मिशन। मार्क केली के साथ जुड़वां बच्चों पर अध्ययन।

जेफ विलियम्स
543 दिन
कई आईएसएस मिशन। अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान।

वलेरी पोल्याकोव
437 दिन
अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वालों में नाम शामिल है

सुनीता विलियम्स
560 दिन
से अधिक वह अंतरिक्ष में रह चुकी है। कई मिशन में शामिल रही हैं। अंतरिक्ष में चहलकदमी कर चुकी हैं। उनकी पिछली वापसी में समय लगा था।

बेटा अंतरिक्ष की सैर करेगा, सोचा न था

लखनऊ, मुख्य संवाददाता। शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने बताया कि शुभांशु बचपन में सामान्य बच्चों की तरह ही था। कोई इधर-उधर की बातें नहीं करता था। मैंने भी कभी यह नहीं सोचा था कि वह इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि एयरफोर्स में उसका करियर बेहतर रहेगा और एयर मार्शल तक पहुंचेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अंतरिक्ष की सैर करेगा। चांद-तारों के करीब तक जाएगा।

मां ने आगे बताया कि यह मिशन हमारे लिए खास है, शुभांशु के हर शुभचिंतकों के लिए गौरव का प्रतीक है। यही कामना है कि मिशन सफल रहे और अपने उद्देश्यों को पूरा करे। बेटे के अंतरिक्ष यात्रा में जाने की जितनी खुशी है, उतना ही अंदर से मन घबरा भी रहा है। हम उसके इस मिशन में साथ हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे उस पर बहुत फख्र है, लेकिन फिक्र भी है। हमें यकीन है कि जैसे हमारे बच्चे ने अपने हर काम में सफलता पाई है, इस मिशन में भी उसे कामयाबी ही मिलेगी।

लखनऊ के त्रिवेणीनगर स्थित घर पर बहन शुचि, पिता शंभू दयाल शुक्ला और मां आशा शुक्ला (बाएं से दाएं)।

परिणाम आने पर खीर-रसगुल्ला : मां आशा शुक्ला बहुत खुशी के साथ बताती हैं कि उनका बेटा हमेशा से क्लास के टॉपर में शामिल रहा है। किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आता था और उसमें अच्छे नंबर आने का पता चलता था, तब मैं घर में कभी खीर तो कभी रसगुल्ले बनाकर सबको खिलाया करती थी। वैसे, बचपन में शुभांशु को कभी कोई विशेष व्यंजन ज्यादा पसंद नहीं रहा।

बहनों ने भाई की दृढ़ता, अनुशासन को सराहा

शुभांशु की बहनें याद करती हैं - हम तीनों भाई-बहन छोटे थे, तब मां रात नौ बजे टीवी बंद कर देती थीं। मोबाइल होता नहीं था। टीवी बंद होने के बाद हमलोग कमरे में सोने का नाटक करते थे। कुछ देर बाद हममें से कोई एक धीरे से जाकर टीवी चालू कर देता था। बाकी दो बच्चे गलियारे में थोड़ी दूरी पर खड़े रहते थे कि यदि मम्मी जाग जाएं, तो तुरंत बता दें। उस समय कोई भी शो हो, तीनों बैठकर देखते थे। शुभांशु बचपन से ही बहुत गंभीर था। उसे बचपन से ही अलग और बड़ा करने की चाह थी। शुभांशु हर चीज बहुत सोच-समझकर करता था। शांत रहता था, लेकिन अपने काम से सबको चौंका देता था।

लक्ष्य पूरा होने तक शुभांशु कभी चैन से नहीं बैठता था। बचपन में शुभांशु को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। एनडीए में चयन के बाद शुभांशु की डाइट बिल्कुल बदल गई। अनुशासन बढ़ गया।

(ग्रुप कैप्टन शुभांशु की बहन शुचि मिश्रा और निधि ने बचपन से जुड़े किस्से बताए)

गर्व से बताता हूं, शुभांशु मेरा दोस्त है

शुभांशु और मेरा चार वर्ष की उम्र से याराना है। हमने 12वीं तक साथ पढ़ाई की। यही नहीं, एक ही क्लास और सेक्शन में। हम साथ पढ़े, खेला, शरारतें कीं और आज भी वही रिश्ता बना है। मैं पिछले 22 वर्ष से बेंगलुरू में हूं। पिछले सात वर्ष से शुभांशु भी बेंगलुरु में ही पोस्टेड था।

विशाल श्रीवास्तव
शुभांशु के मित्र

बचपन में मैं लखनऊ के अलीगंज में रहता था और शुभांशु त्रिवेणीनगर में। दोनों मोहल्ले आसपास हैं। 2002 में 12वीं करने के बाद हम दोनों अलग रास्ते चले, लेकिन फोन पर संपर्क बना रहा। हम दोनों के विचार मिलने के कारण पारिवार जैसा रिश्ता आज भी बना हुआ है। उनके बेटे और मेरी बेटी की उम्र में दो महीने का अंतर है। उनकी पत्नी मुझे भाई कहती हैं और बेटा मामा। पढ़ाई के लिए हम अलग हुए थे, लेकिन सात वर्ष से तो एक ही शहर में हैं।

मैं यहां 22 वर्षों से काम कर रहा हूं। यह संयोग ही है कि शुभांशु की पोस्टिंग बेंगलुरु में हो गई। सात वर्ष से वह भी यहीं तैनात है। जब शुभांशु की पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई, तो मैं अपने परिवार के साथ दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। शुभांशु के आने के बाद दो सप्ताह रुका रहा। उनका परिवार घर की व्यवस्था होने तक हमारे साथ रहा। संयोग कुछ ऐसा बना कि मैं दुबई से फिर परिवार के साथ बेंगलुरु लौट आया। इस बार मेरा परिवार उनके साथ रहा। आज जो भी मिलता है, गर्व से बताता हूं कि शुभांशु मेरा दोस्त है।

हम लोगों की शरारतें भी लोगों को अब पता चल रही हैं। एक बार शुभांशु स्कूटी चला रहा था और दुर्घटना हो गई। अब चिंता इस बात की हुई कि घर में बताना पड़ेगा और डांट पड़ेगी। शुभांशु ने घर पहुंचकर कहा कि स्कूटी विशाल चला रहा था। मेरी छवि सीधे बच्चे की थी, तो आसानी से माफ कर दिया गया। हमारे बीच में ऐसी कई कहानियां हैं, जो हम दोनों ही जानते हैं।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध और वाद-विवाद से बचें। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें।

वृष : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में आय में वृद्धि होगी। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

मिथुन : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। माता-पिता का सान्निध्य मिलेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

कर्क : मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध और व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। कारोबार में बदलाव हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा।

सिंह : मन अशांत रहेगा। संयत रहें। क्रोध से बचें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत भी रहें। कारोबार का विस्तार हो सकता है। परिवार से दूर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव हो सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

धनु : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल होंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार के लिए दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।

कुंभ : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

11 जून, बुधवार, शक संवत् : 21 ज्येष्ठ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 28, ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 14 जिल्हिजा, 1446, विक्रमी संवत् : ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा दोपहर 01.14 मिनट तक पश्चात् प्रतिपदा तिथि। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 08 बजकर 11 मिनट तक पश्चात मूल नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात्रि 08.11 मिनट तक, उपरांत धनु राशि। सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। ज्येष्ठ पूर्णिमा। संत कबीर जयंती। ज्येष्ठी योग। गण्डमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मैं मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ा हूं। पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि मेरी लोकप्रियता में कमी आ रही है। कृपया इसका कोई समाधान बताएं? -मिहिर, दिल्ली

- आप के घर के नक्शे के अनुसार आपने अपने घर की पूर्व दिशा मे एक कूड़ेदान एवं लोहे की अलमारी रखी है, जो समस्या का कारण है। इस कूड़ेदान और अलमारी को यहां से हटा दें। एक कुर्सी यहां पर रखकर प्रतिदिन कुछ समय यहां पर व्यतीत करें।
- आपको जो भी अवॉर्ड्स मिले हैं, इनमें से कुछ अवाइर्स इस स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो मोबाइल भी इसी स्थान पर चार्ज करें। प्रयास करें कि जब भी पानी पियें तो ताम्बे के गिलास में ही पियें। अपने बायें हाथ में एक सन स्टोन का ब्रेसलेट पहनें।

वर्ग पहेली : 7993

बाएं से दाएं

1. आवंटित करना; बांटना; देना; हिस्से करना (4,3)
6. चलाने वाला; ढोने वाला; वहन करने वाला (4)
8. पीछा करते हुए दूर तक भगाना; डरा धमका कर दूर भगाना; हटाना (4)
9. अनुभव करना; जान लेना; प्राप्त करना (2)
10. अंदाज; अटकल; अनुमान (3)
13. नाड़ी; डंठल; फूल की डंडी; पोली नली; घोड़ों की टाप (2)
14. आह भरना; कुढ़ना; बिसूरना; विलाप करना (4)
15. डरना; भयभीत होना; सिमटना (4)
17. बुरी नजर के असर को खत्म करना; बुरी दृष्टि के प्रभाव को उतारना (3,4)

ऊपर से नीचे

2. कड़कते घी में डालकर पकवाना (4)
3. पुर्जा; मशीन; यंत्र; युक्ति; आने वाला दिन (2)
4. अपनाना; नामकरण करना; मंत्र देना (2,2)
5. अत्यधिक श्रम होना; ताप या परिश्रम के कारण शरीर से जल-कण निकलना (3,4)
6. ठीक करना; पूर्ण करना; प्रकाशन योग्य बनाना; संपन्न करना (4,3)
7. कंचन; स्वर्ण; धतूरा (3)
11. भावपूर्ण; मधुर; मीठा; रसीला (3)
12. आश्रम; उद्यान; चमन; फुलवारी (4)
13. जिसका बड़ा नाम हो; नामवर; प्रसिद्ध (4)
16. अतिकाल; विलंब (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 7992

1 ड	■	2 ब	द	3 ह	वा	4 स	■	5 इ
6 ग	ला	ना	■	त्या	■	जा	■	ध
म	■	व	■	■	7 अ	व	ता	र
गा	■	8 ट	9 ल	ना	■	ट	■	उ
10 क	र	■	ता	■	11 सैं	■	12 व्या	ध
र	■	13 अ	■	14 अ	झा	15 ते	■	र
16 च	क	रा	ना	■	■	ड़	■	क
ल	■	ज	■	17 ली	■	18 पं	थ	र
ना	■	19 फ	सै	ला	हो	ना	■	ना

सुडोकू : 7975

*आसान

9		8				2		3
	4			9			6	
7			8		1			4
			4		9			
8			5		6			1
			3		2			
3			2		8			9
	8			6			4	
1		2				5		6

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7974

5	6	8	9	7	4	3	2	1
4	7	9	2	3	1	8	5	6
3	1	2	8	6	5	4	7	9
6	8	7	4	2	9	5	1	3
9	4	5	6	1	3	2	8	7
2	3	1	7	5	8	6	9	4
7	2	4	5	9	6	1	3	8
1	5	6	3	8	7	9	4	2
8	9	3	1	4	2	7	6	5

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 11 जून 2025

नियति से भेंट

Axiom Mission-4 के तहत उड़ान भरने जा रहे शुभांशु शुक्ला के साथ देश के 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें और महत्वकांक्षाएं भी उड़ान भरेंगी। इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन का यह सफर देश के लिए अंतरिक्ष के नए दरवाजे खोलेगा, जिसकी छाप आने वाले अभियानों पर दिखेगी।

कमी पूरी हुई । सोवियत सोयुज स्पेसक्राफ्ट में बैठकर राकेश शर्मा साल 1984 में जब स्पेस में पहुंचे थे, तब से 41 बरस हो चुके हैं। शुभांशु दूसरे भारतीय होंगे, जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चार दशक के इस लंबे अंतराल में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अद्भुत कामयाबियां हासिल की हैं। अमेरिका, रूस, चीन समेत वह दुनिया की बड़ी स्पेस पावर में शुमार हो चुका है। मिशन चंद्रयान और आदित्य ने उसे अलग लीग में ला खड़ा किया है, फिर भी एक कमी थी, जो अब शुभांशु की यात्रा से पूरी हो रही है।

शुभांशु जाएंगे स्पेस स्टेशन

अनुभव का फायदा । राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु तक, भारत के लिए स्पेस में बहुत कुछ बदला है। तब वह शुरुआत थी, इंफ्रा और तकनीक की कमी थी। इसी वजह से दूसरे भारतीय को स्पेस तक जाने के लिए 2025 तक का इंतजार करना पड़ा। लेकिन, इन बीते बरसों में तकनीक, हुनर और संसाधन - सभी मोर्चों पर काम किया गया है। ISRO की पहचान ऐसी स्पेस एजेंसी के रूप में बन चुकी है, जो कम खर्च में बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। ऐसे में ISS पर रहकर शुभांशु जो कुछ भी सीखेंगे, उसका फायदा आगे मिलेगा।

बड़े कदमों पर नजर । भारत अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन 'गगनयान' पर काम कर रहा है। सब कुछ सही रहा तो 2027 में देश अपने दम पर अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। इसके बाद का अगला बड़ा लक्ष्य है 2035 तक अपना पहला स्पेस स्टेशन खोलना और 2040 तक चांद पर इंसान को भेजना। इन दोनों और भविष्य के सभी अभियानों के लिए शुभांशु का अनुभव बहुमूल्य साबित होगा।

फायदा उठाने का मौका । Axiom Mission-4 के मायने इसलिए भी बहुत हैं, क्योंकि इसने स्पेस और साइंस को लेकर उत्सुकता पैदा कर दी है। अब सरकार पर है कि वह इसका फायदा किस तरह उठाती है। अभी पूरे देश में केवल 26 साइंस म्यूजियम हैं, जो किसी नजरिये से काफी नहीं कहे जा सकते। सरकारी मदद से विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार भी धीमी है। मौजूदा स्पेस जर्नी इन चीजों को गति देने का अवसर है। शुभांशु शुक्ला इस समय सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीयों में से एक हैं। पूरा देश जुड़ाव महसूस कर रहा है उनसे। उनकी सफलता पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

ऑफबीट

ऐप और रिश्ते

सौरभ श्रीवास्तव

कुछ रोज पहले उत्तराखंड जाना हुआ। ठिकाना था, सतखोल का प्योड़ा गांव। वहां हमारे एक अजीज दोस्त रहते हैं। मिलने के उत्साह में उन्होंने कहा कि वह मुझे लेने काठगोदाम स्टेशन आएंगे। मैंने कहा कि तकल्लुफ की जरूरत नहीं, पर वह नहीं माने। खैर, ट्रेन सुबह आठ बजे स्टेशन पहुंची। वह अपनी कार के साथ मुझे स्टेशन के बाहर मिले। एक-दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे।

चाय-नाश्ता करने के बाद हम कार में बैठे तो बोले- कुछ देर रुक कर चलते हैं, जरा बाजार खुल जाए। मुझे कुछ सामान लेना है। मुझे भी कौन सी जल्दी थी। हम कुछ देर बतियाते रहे फिर उन्होंने कार हल्द्वानी की ओर मोड़ दी। मेन मार्केट की कुछ दुकानें खुलने लगी थीं। उन्होंने कार किनारे पार्क की और हम खरीदारी करने बढ़ गए। उन्होंने एक लिस्ट निकाली, जिस पर लिखा था-भट्टदा की दवा, सुमन चाची की सब्जियां, कर्नल साब के लिए किताब आदि-आदि। उन्होंने बड़ी ही तल्लीनता से सारा समान जुटाया और कार पहाड़ की ओर मोड़ दी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। घर से सौदा लेने निकलता था तो कभी बगल वाली चच्ची के लिए खीरा तो कभी सामने वाली बुआ के लिए बेसन लेकर लौटता था। आखिर कैसा था, मोहल्ले का सामाजिक ताना-बाना और कैसा है पहाड़ पर दुर्गम इलाके में रहने वाले लोगों का आपसी सामंजस्य?

शहरों में अब तो क्विक डिलिवरी ऐप पर ज्यादातर चीजें उपलब्ध हैं। पैसा कुछ ज्यादा खर्च होता है पर जीवन आसान लगता है, लेकिन असल में हो कुछ और रहा है। हमारी सामाजिकता, पड़ोसियों से हमारे संबंध का क्षरण। अब इसे दुर्गम इलाकों की मजबूरी कहें या मोहल्ले का समाजशास्त्र, दोनों ही जगहें जरूरतें साझा करने से रिश्ते गाढ़े होते थे। कॉलोनियों या फ्लैट वाली सोसायटियों में शायद ही ऐसा होता हो कि कोई किसी के बच्चे से काम कह दे। कह दे तो उसके माता-पिता के बुरा मान जाने की आशंका काफी है। मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए जो विकास हुआ है, उसने हमें अकेलेपन के कोटर में ढकेल दिया है। लोग अपने काम से काम रखते हैं और अपनी दुनिया से विरले ही कदम बाहर निकालते हैं, पर बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ अपने काम से काम रखने से सुखद जीवन जिया जा सकता है। अपने लिए, जिए तो क्या जिए... गाना गुनगुनाते हुए सोचिएगा।

एकदा

छपाई से लगाव

19वीं सदी में अमेरिका में लेखक, हास्यकार, उद्यमी, प्रकाशक और व्याख्याता के तौर पर एक नाम प्रसिद्ध था- Samuel Langhorne Clemens। उन्हें दुनिया मार्क ट्वेन के नाम से भी जानती है। एक लेखक और वक्ता के तौर पर जब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी अमेरिका में छपाई की मशीनों का उद्योग भी करवट ले रहा था। किताबों की दुनिया से मार्क का इतना लगाव था कि उनका ध्यान Paige Compositor की तरफ गया। दावा किया जा रहा था कि इस मशीन से छपाई की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। मार्क ट्वेन भी प्रभाव में आ गए और अपनी पूरी कमाई और पत्नी की सारी दौलत इसी मशीन पर लगा दी। लेकिन 10 वर्ष के अंदर उनका दिवाला निकल गया। कर्ज चुकाने के लिए घर तक बेचना पड़ा। हालांकि किताब लिखने और व्याख्यान देने का काम उन्होंने जारी रखा, जिससे उनके दिन सुधरने लगे। मार्क ट्वेन जब दोबारा संभले, तब तक उनकी खरीदी मशीन को लोग भूल भी चुके थे। लेकिन, उन्होंने उस मशीन को आजीवन अपने पास रखा। उनके घर और मशीन को देखने के लिए आज भी पर्यटक हार्टफोर्ड जाते हैं। और मार्क ट्वेन को आज अमेरिकी साहित्य का जनक कहा जाता है।

Subrata Dhar

संकलन : हरि प्रसाद राय

AI 2027 रिपोर्ट AGI और सुपरइंटेलिजेंस की दौड़ के ख़तरों की भयावह तस्वीर दिखाती है

इंसान से बेहतर हों मशीनें तो क्या होगा

आनंद प्रधान

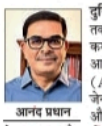

दुनिया एक और बड़ी तकनीकी छलांग के कगार पर है। जहां अभी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) खासकर जेनरेटिव AI के प्रदर्शन और प्रभाव को हैरत से देखा जा रहा है, वहीं टेक कंपनियां उससे आगे आर्टिफिशल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) या आर्टिफिशल सुपरइंटेलिजेंस (ASI) की दौड़ में जुटी हुई हैं। AGI का अर्थ है कि जब मशीन एक मनुष्य की तरह वे सभी काम करने लगेगी, जिसमें सिर्फ मनुष्य सक्षम है। सुपरइंटेलिजेंस में मशीन बौद्धिक रूप से मनुष्य से भी ज्यादा सक्षम हो जाएगी।

AI पर दावे । यह परिदृश्य काल्पनिक लगता है, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों का दावा है कि अगले पांच वर्षों में यह संभव है। हालांकि AGI या ASI की कल्पना अभी सैद्धांतिक स्तर पर ही है। लेकिन जिस तरह से बड़ी टेक/AI कंपनियां कंप्यूटर की प्रॉसेसिंग क्षमता, AI एजेंटों में सफल क्षमताओं और पुनरावर्ती आत्म-सुधार के साथ उनकी ट्रेनिंग पर अरबों डॉलर बहा रही हैं, उसे देखते हुए इन दावों को सिर्फ कल्पना की उड़ान मानना भूल होगी।

AGI कुछ साल दूर । इस सिलसिले में AI फ्यूचर्स प्रॉजेक्ट की ओर से जारी 'AI 2027' रिपोर्ट मानती है कि AGI कुछ साल दूर है। रिपोर्ट OpenAI में काम कर चुके डैनियल कोकोतेलो और उनके चार अन्य साथियों ने मिलकर लिखी है। यह दावा करती है कि इस सुपर मानवीय AI का दुनिया पर अगले एक दशक में जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है।

मशीनों के युग में कैसी हो हमारी तैयारी
- आने वाले कुछ वर्षों में सुपरइंटेलिजेंट मशीनें बन सकती हैं
- भविष्य में कई अहम काम रोबॉट्स के हाथों में जाने का डर है
- सुपरइंटेलिजेंट मशीनों के वैश्विक नियमन की भी है जरूरत

खुद से बेहतर एजेंट । रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI के मौजूदा ChatGPT-4 से बहुत आगे के AI एजेंट-1 और एजेंट-2 सिस्टम अभूतपूर्व कम्प्यूटेशनल निवेश और सिंथेटिक डेटा के जरिए जल्दी ही AI विकास को ऐसी गति देंगे कि वह प्रभावी रूप से एक खुफिया विस्फोट की शुरुआत की तरह होगा। उदाहरण के लिए, एजेंट-2, एल्गोरिदमिक प्रगति को तिगुना कर सकता है। यह बिना मानवीय हस्तक्षेप के खुद एक विशेषज्ञ AI शोधकर्ता की तरह काम कर सकता है और अपने से बेहतर एजेंट तैयार करने में अगुआ भूमिका निभा सकता है।

मशीन सुझाएगी रणनीति । वह अगले कुछ महीनों और सालों में अपने से बेहतर और काफी हद तक स्वायत्त और स्वचालित एजेंट-3, फिर एजेंट-3 कुछ महीनों के अंतराल पर और अधिक ताकतवर एजेंट-4 और 2028 आते-आते एजेंट-4 सुपर-इंटेलिजेंट एजेंट-5 पैदा कर देगा। एजेंट-5 अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जीनियसों से भी तेज होगा।

आधुनिक हथियार । एक समय आएगा जब वह एक तरह से सरकार को नियंत्रित करने लगेगा। उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसे सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स सौंप दिया जाएगा। आधुनिक हथियारों के निर्माण, सैन्य इंटेलिजेंस के विश्लेषण, स्वचालित कमांड और कंट्रोल और दुश्मन देश में जासूसी, वहां मुखबिर बनाने और हैकिंग जैसे काम उसके पास आ जाएंगे।

रोबॉट इकॉनमी । दूसरी ओर, ज्यादातर काम रोबॉट्स के पास चला जाएगा। यह रोबॉट अर्थव्यवस्था होगी, जिसमें फैक्ट्रियों से लेकर कृषि और सेवा क्षेत्र में सारा काम एजेंट-5 से स्वचालित रोबॉट कर रहे होंगे। ज्यादातर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। लेकिन उन्हें पर्याप्त यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल रही होगी।

इंसानों से टकराव । रोबॉट धीरे-धीरे खेतों, समुद्रों, पहाड़ों से लेकर फैक्ट्रियों और स्पेशल इकॉनमिक जोन्स (SEZ) से निकलकर मनुष्यों की बस्तियों में फैलने लगेंगे। फिर 2030 के मध्य तक एक समय ऐसा आएगा, जब उन रोबॉट्स को लगेगा कि मनुष्य उनके फैलाव में बाधा बन रहे हैं तो वे तेजी से फैलने वाले कोई आधा दर्जन जैव हथियार विकसित करके इंसानों की बस्तियों में छोड़ देंगे, जिससे कुछ ही घंटों में धरती से इंसानी आबादी खत्म हो जाएगी।

दोधारी तलवार । यह कोई विज्ञान कथा नहीं है बल्कि AI/टेक उद्योग के मुनाफे की भूख और प्रतियोगिता में आगे रहने की होड़, भू-राजनीति के दांवपेचों और AI विकास पर प्रभावी नियमन और शासन के अभाव से आकार लेने वाली एक वास्तविकता है। सुपरइंटेलिजेंट AI एक दोधारी तलवार है। सुपरइंटेलिजेंट AI के उत्पादकता लाभ बहुत हैं लेकिन संक्रमण काल झटकों से भरा और अव्यवस्थित होगा। इसमें कमजोर डिजिटल बुनियादी ढांचे या शिक्षा प्रणाली वाले देशों के पीछे छूट जाने का जोखिम है।

क्या हों उपाय । इसलिए रिपोर्ट AI को सुरक्षित बनाने और मानवीय नियंत्रण में रखने के लिए वैश्विक पहल और उपाय के सुझाव देती है। जैसे, AI हथियारों की दौड़ से निपटने के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण की तरह के बहुपक्षीय प्रयास। बड़ी टेक/AI कंपनियों को 'AI दौड़ में पीछे छूट जाने' का डर दिखाकर मनमानी की खुली छूट देने के बजाय उन पर कड़े नियमन और निगरानी की जरूरत है। सवाल यह है कि इन खतरों को क्या दुनिया मूकदर्शक की तरह देखती रहेगी या इसे अपने नियंत्रण में लेगी।

(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, ढेंकानाल में पत्रकारिता के प्रफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

जासूसों की अंधेरी दुनिया

पिछले दिनों पंजाब से एक और यूट्यूबर जसबीर सिंह को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी भी काफी चर्चा में रही। जासूसों के पकड़े जाने के बाद क्या होता है? क्या ये छूट भी जाते हैं? कानून में क्या कायदा है? आइए, समझते हैं :

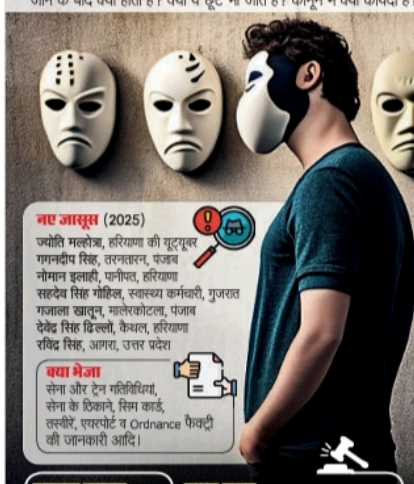

नए जासूस (2025)
ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की यूट्यूबर
गगनदीप सिंह, तरनतारन, पंजाब
नोमान इलाही, पानीपत, हरियाणा
सहदेव सिंह गोहिल, स्वास्थ्य कर्मचारी, गुजरात
गजाला खातून, मालेरकोटला, पंजाब
देवेंद्र सिंह ढिल्लो, कैथल, हरियाणा
रविंद्र सिंह, आगरा, उत्तर प्रदेश

क्या भेजा
सेना और ट्रेन गतिविधियां, सेना के ठिकाने, सिम कार्ड, तस्वीरें, एयरपोर्ट व Ordnance फैक्ट्री की जानकारी आदि।

कायदा कानून
- ऑफिशल सीक्रेट एक्ट के तहत होती है गिरफ्तारी
- 1923 में लागू हुआ OSA, 1967 में अपडेट
- 2006 ARC और 2015 समिति ने अपडेट सुझाया
- अभी तक कोई बदलाव नहीं

मान्य सबूत
- स्केच, योजनाएं, और दस्तावेज
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के तहत प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक डेटा

अमान्य सबूत
- धारा 65B प्रमाणन के बिना वट्सऐप चैट या अन्य डिजिटल डेटा
- RTI एक्ट, 2005 के तहत सार्वजनिक जानकारियां
- एन्क्रिप्टेड या डिलीट किया गया डेटा

सजा के नियम
- धारा 3, 4, 5 के तहत 3 साल से लेकर उम्रकैद
- दुर्लभ मामलों में मौत

धरपकड़

वर्ष	संख्या
2014	11
2015	9
2016	30
2017	18
2018	40
2019	40
2020	39
2021	55
2022	55

सजा का हाल

2022: 98.5% केस कोर्ट में लंबित (NCRB 2023)

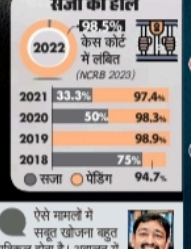

वर्ष	सजा	पेंडिंग
2021	33.3%	97.4%
2020	50%	98.3%
2019		98.9%
2018	75%	94.7%

कुख्यात केस

पाकिस्तान के लिए
1978: सांबा स्पाई केस- 50 सैन्य कर्मी पकड़े
2010: माधुरी गुप्ता, कूटनीतिज्ञ
2015: रंजीत, वायुसेना
2021: हरप्रीत सिंह, गुरभेज सिंह सैन्यकर्मी
2023: प्रदीप कुरुलकर, DRDO के वैज्ञानिक
2025: संदीप सिंह, सैन्यकर्मी

अमेरिका के लिए
1980: के.वी. उन्नीकृष्णन, RAW अधिकारी
2004: रबिंदर सिंह, RAW अधिकारी, फरार

चीन के लिए
2007: रवि नायर, RAS अधिकारी
2020: पत्रकार राजीव शर्मा

रूस के लिए
2008: कमोडोर सुखजिंदर सिंह, नौसेना अधिकारी

अन्य
1985: कुमार नारायण- PMO से फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के लिए

OSA आजादी से पहले का है। RTI एक्ट भी इसका दायरा संकुचित करता है। सबूतों की प्रकृति भी समय के साथ बदल चुकी है। इसलिए यह कानून संशोधन की मांग करता है। - नितिन मिश्रा, एडवोकेट

पाकिस्तान लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनका शोषण करता है। लोग हमेशा इसकी रिपोर्ट नहीं करते और अपने देश की जानकारी पाकिस्तान को देते रहते हैं। - मेजर जनरल अशोक कुमार (रि.)

ऐसे मामलों में सबूत खोजना बहुत मुश्किल होता है। अदालत में सब कुछ डॉक्यूमेंट्री सबूत पर ही टिका होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सिद्ध करना काफी मुश्किल होता है। - अशोक कुमार, पूर्व डीजीपी

कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक: गौरव

सरकारी लहजे का फ़ायदा उठा रहे स्कैमर

पार्थ सिन्हा

इस समय आप देश में किसी को भी कॉल करके देखिए - अपने CA, किसी रिश्तेदार या फिर डॉक्टर को - पहली घंटी बजने के पहले ही सरकार की तरफ से जारी एक संदेश सुनाई पड़ता है। इसमें चेतावनी दी जाती है कि डिजिटल स्कैम से सावधान रहें। इसकी शुरुआत होती है कि सतर्क रहें। अगले 95 सेकंड तक संदेश सुनने वाला सतर्क ही रहता है, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड, OTP और एहतियाती कदमों के बारे में बात होती है। यह केवल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, स्टेट का मूड भी है- उनींदा-सा, थोड़ी चेतावनी देने वाला, थोड़ा चिढ़ाने वाला। लेकिन विडंबना है कि सरकार हमें जिस आवाज में सतर्क करती है, साइबर ठग उसी आवाज में हमें निशाना बनाते हैं।

एक्टिंग है हथियार । भारत में अब स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार एक्टिंग है। पुलिस के नाम से कॉल आते ही लोग सन्न रह जाते हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होता, लेकिन फोन करने वाले की आवाज अपराधी होने का एहसास करा देती है।

सरकारी टोन । साइबर ठगों को बहुत थोड़ी चीजें चाहिए - एक बर्नर फोन, फर्जी बैज, सरकारी जैसी दिखने वाली मुहर और ऐसी आवाज, जिसे सुनकर ऐसा लगे कि वह हमेशा नाराज है। वे सरकारी सिस्टम के शब्द, उसकी आवाज, टोन, हावभाव को अपनाते हैं। वे इसलिए सफल नहीं हैं, क्योंकि उनकी तकनीकी समझ शानदार है - वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही काम करते हैं। यह मामला डिजिटल निरक्षरता का नहीं, इमोशनल कंडिशनिंग का है।

डराने वाली भाषा । दशकों से भारतीय राज्य एक सहयोगी नहीं, बल्कि डांटने-फटकारने वाले बॉस की तरह संवाद करता आया है। सरकारी दस्तावेज अदालती समन की याद दिलाते हैं। फॉन्ट ऐसे चुने जाते हैं, जो अदालती समन की याद दिलाएं। नोटिस का मकसद जानकारी देना नहीं, भय पैदा करना लगता है। आज जब हमारे कानून आधुनिक हो रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाएं डिजिटल, तब भी सरकारी भाषा की टोन टाइपराइटर के युग की बनी हुई है।

AI Image

कॉमन रूम

भय का ढांचा । आशीष नंदी ने कहा था कि भारत में औपनिवेशिक शक्ति को खत्म नहीं किया गया, उसे बस घरेलू रूप दे दिया गया है। वायसराय अब कलेक्टर बन गए हैं, रानी की अंग्रेजी एफिडेविट की हिंदी में तब्दील हो गई है। लेकिन, भय का भावनात्मक ढांचा अब भी पहले की तरह बना हुआ है। आज के स्कैमर इसी का फायदा उठाते हैं। उन्हें डर और चिंता पैदा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें यह विरासत में मिलता है। वे थोड़ी-सी धमकी देते हैं और आम नागरिक झुक जाता है।

बदलाव चाहिए । यह भी विडंबना है कि जिस स्टेट ने हमें इस भाषा से डरना सिखाया, वह कह रहा है कि शांत रहो और किसी पर भरोसा न करो। जिन लोगों को आदेश का पालन करने की ट्रेनिंग दी गई हो, उन्हें आप शक करना नहीं सिखा सकते। आप उसी लहजे में शांत रहने के लिए नहीं कह सकते, जिस लहजे में कभी तहसीलदार के दफ्तर से समन आया था। इसका यह मतलब नहीं है कि इन अपराधों के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि उसने जिस चीज का दिखावा किया था, वह अब सार्वजनिक संपत्ति बन चुकी है। अब कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका उपाय कोई अभियान नहीं है, हमें सांकेतिक बदलाव करने की जरूरत है। सोचना होगा कि सत्ता किस तरह बात करती है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

त्रिकालदर्शी बना देता है तीनों काल का त्याग

सुरक्षित गोस्वामी

काल और काल को देखने वाली दो अलग-अलग चीजें हैं। जो साकार है, प्रकट हो गया, जिसका जन्म हुआ है, जो पैदा हुआ, जो बना है वो काल से बंध जाता है, क्योंकि बनने के साथ टूटना और जन्म के साथ मौत निर्धारित हो जाती है। काल एक सीमा है, जो केवल मौत तक यात्रा कराता है! इसलिए मौत के देवता को महाकाल कहते हैं। जब काल को गहराई से देखते हैं और उसको समझते हैं तो एक काल वह है, जो घड़ी में है। एक काल हमारे मन में है। हमारे मन का काल घड़ी के काल से अलग होता है। इसलिए दुख को झेलते और इंतजार करते समय छोटा-सा वक्त भी बहुत लंबा लगने लगता है। इसी तरह सुख के समय लंबा वक्त भी छोटा लगता है।

हर व्यक्ति के मन का काल अलग होता है। ब्रह्मांड दृष्टि से उसका काल अलग तरह से परिभाषित है, ब्रह्मा का काल अलग है। चींटी और मच्छर का काल मनुष्यों के काल से बिल्कुल अलग है। मनुष्य की बात करें, तो पाएंगे कि यहां काल तीन प्रकार के होते हैं - एक जो बीत गया, भूतकाल यानी past, दूसरा जो बीत रहा है, वर्तमान यानी present और तीसरा जो आएगा, भविष्य यानी future। देखा जाए तो तीनों काल केवल मन की कल्पना हैं।

सूर्य में कोई काल नहीं होता, दिन-रात नहीं होता! न उसका अतीत है और भविष्य, बस वह चलता रहता है। अगर व्यक्ति अतीत की बातों को याद करके दुखी होता रहे तो समझना चाहिए कि उसका past जाग गया है और वह उसकी मेमरी का हिस्सा बन गया है या यूं कहें, मेमरी ही बन गई है। ऐसे में पास्ट बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा और वह अपने पास्ट से हट नहीं पाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका साक्षी नहीं हो पाएगा। साथी होने का अर्थ यही है कि हर काल में स्वयं को तलाशने की जरूरत नहीं, बल्कि उका सक्षी बनना है। साक्षी हुए बिना अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। ऐसा व्यक्ति दुखी और डिप्रेस रहता है। एक भविष्य में ही मन को टिकाये रखता है और शेखचिल्ली की तरह कल्पना के ख्यालों में जीवन जीने लगता है। ऐसा व्यक्ति डरा और लोभी हो जाता है। इसके लिए भविष्य का साक्षी होना जरूरी है।

भूत और भविष्य के बीच दौड़ने वाला इंसान वर्तमान को एंजॉय नहीं कर सकता। क्योंकि उस व्यक्ति की चिताओं में बस काल घूमता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति तीनों कालों में उलझ जाता है। कभी भूतकाल हावी होता है और कभी भविष्य काल। लेकिन एक और अवस्था हमारे भीतर है, जिस पर काल का असर नहीं पड़ता। शरीर काल से बंधा है, लेकिन आत्मा कालातीत है। काल का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। जब इसी आत्मभाव में आकर हम तीनों कालों को देखते हैं, तब हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। जहां किसी भी काल में हम अटकते नहीं, फंसते नहीं।

कल्पमेधा

सफल होने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरुआत करते हैं, बल्कि आपका उद्देश्य कितना ऊंचा है, इससे फर्क पड़ता है।

– नेल्सन मंडेला

खसरे का खतरा

खसरे का संक्रमण एक बार फिर अपने पांव तेजी से पसार रहा है। यह किसी एक देश की बात नहीं, बल्कि दुनिया भर में खसरे के मामले बढ़ रहे हैं। इससे संबंधित एक हालिया रपट ने विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इसके मुताबिक, वर्ष 2023 में पूरी दुनिया में खसरे के एक करोड़ तीन लाख मामले सामने आए, जो 2022 की तुलना में 20 फीसद अधिक हैं। इसे अमेरिका, यूरोप, भारत और आस्ट्रेलिया सहित कई देशों के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। खसरा सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है और इसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। मगर सवाल यह है कि जब दुनिया भर में इस संक्रमण का टीका वर्षों से उपलब्ध है, तो इसकी चाल फिर तेज क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर खसरे से निपटने के उपायों में ढिलाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

गौर करने वाली बात है कि खसरे से बचने के लिए तैयार किया गया टीका वर्ष 1963 से ही दुनिया भर में उपलब्ध है और इसके प्रभावशाली नतीजे भी सामने आए हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसके संक्रमण के मामले बढ़ना भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए एक चेतावनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था सेंटर फार डिजीज कंट्रोल (सीडीसीसी) की एक के अनुसार, भारत उन 57 देशों में से एक है, जहां वर्ष 2023 में खसरे के मामले बढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर इस संक्रमण के फैलने की घटनाएं 20 फीसद बढ़ी हैं। अमेरिका में तो वर्ष 2000 में खसरे के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन पच्चीस साल बाद वहां की स्वास्थ्य संस्था सीडीसी ने इस साल जनवरी से मई तक देश में खसरे के 900 मामले सामने आने की पुष्टि की है। आस्ट्रेलिया में इस साल के शुरुआती पांच महीनों में खसरे के 77 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2024 में यहां कुल 57 मामले सामने आए थे। यूरोप में पिछले 25 वर्षों की तुलना में खसरे के सबसे अधिक मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया भर में खसरे के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट में कहा गया है कि कोरोना महामारी भी खसरे का संक्रमण बढ़ने की एक वजह बनी है। उस दौरान लोगों का ध्यान कोरोना के टीके लगवा कर इससे बचने पर था। इससे खसरे का टीकाकरण प्रभावित हुआ। मगर, यह भी सच है कि कोरोना काल के बाद सरकारी स्तर पर खसरे के संक्रमण को रोकने को लेकर जो सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी, उसका अभाव रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, खसरे से संक्रामित व्यक्ति कई लोगों में संक्रमण फैला सकता है। लिहाजा दुनिया के लिए यह सावधान होने की घड़ी है। व्यापक स्तर पर टीकाकरण के बिना इस बीमारी से सुरक्षा पाना मुश्किल है। इस रपट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सलाह दी है कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को टीके की दो-खुराक अवश्य मिले।

लापरवाही की लपटें

दिल्ली अनियोजित विकास की एक ऐसी तस्वीर है, जहां हमें एक तरफ झुग्गियां दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर गगनचुंबी इमारतें। नतीजा यह कि यहां सघन बस्तियों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने से बड़े नुकसान का जोखिम हमेशा बना रहता है। भीषण गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। यहां आधुनिक कही जानी वाली कई मंजिलों वाली रिहायशी इमारतें बनाने की इजाजत तो दी गई, लेकिन वहां अग्नि सुरक्षा इंतजामों में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, उसका खमियाजा अब उनमें रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इन इमारतों में आग बुझाने के उपकरण जरूर लगाए गए, पर इसकी जांच-परख महीनों तक नहीं होती। द्वारका में मंगलवार को जिस बहुमंजिला इमारत में आग लगी, वहां अग्नि शमन के पुख्ता उपाय किए गए होते, तो एक पिता और उसकी बेटी तथा भतीजे की मौत न होती। दरअसल, आग की इस घटना के वक्त लपटों से बचने के लिए इन तीनों को जब कोई विकल्प नहीं सूझा तो वे बालकनी से नीचे कूद गए और उनकी जान चली गई।

इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? यह निराशाजनक है कि इमारतों में अग्निशमन के सामान्य उपकरणों को ही पर्याप्त मान कर अधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र दे देते हैं। द्वारका की जिस इमारत में आग लगी, उसकी नीचे की मंजिलों पर लोग खिड़कियां तोड़ते और बालकनी से बचाने की गुहार लगाते देखे गए। इससे साबित होता है कि इमारत की सभी मंजिलों पर आग से बचाव के लिए कारगर उपाय नहीं किए गए थे। यह जानते हुए भी कि न केवल रिहायशी, बल्कि औद्योगिक इलाकों में हर वर्ष आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो रोकथाम के उपाय पहले ही क्यों नहीं किए जाते? समय-समय पर जांच क्यों नहीं होती कि उपकरण काम कर भी रहे हैं या नहीं? बार-बार ऐसे हादसे न हों, इसके लिए अब जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

बाल श्रम के जाल में उलझा बचपन

बाल श्रम के खिलाफ उठने वाली आवाज यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी विकास के इस दौर में करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने पर विवश क्यों हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्वभर में बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।

रिपुदमन सिंह

बाल श्रम एक ऐसी गंभीर समस्या है, जो बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा और सुनहरा भविष्य छीन लेती है। यही नहीं, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास भी बाधित होता है। जबकि, हमें एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहां काम नहीं, किताबें बच्चों का अधिकार हों। बाल श्रम के विरुद्ध आज भी दुनिया भर में आवाज उठती है। विश्व में इस दिशा में चल रहे सतत संघर्ष का ठोस परिणाम कम ही दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। बाल श्रम के खिलाफ उठने वाली आवाज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के इस युग में करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने के लिए विवश क्यों हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, आज भी 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्व भर में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा है। यह स्थिति विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे उस अंधकार को उजागर करती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं।

बाल श्रम एक ऐसा कार्य है, जो बच्चों से उनका बचपन बेहद ही निर्ममता से छीन लेता है। कई बार काम के दौरान उन पर जोर-जुल्म होता है। नतीजा यह कि इन सब हालात के बीच उनका शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास बुरी तरह बाधित होता है। उनके भविष्य की सभी संभावनाएं क्षीण होने लगती हैं। दरअसल, बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है। कई मामलों में पाया गया कि जो बच्चे पढ़-लिख कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं, उन्हें बाल श्रम का जाल अंधकारमय भविष्य की ओर ले जाता है। इस समस्या की जड़ में गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, परिवार में बेरोजगारी और बाल श्रम कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन है। जब एक परिवार की रोजी-रोटी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तब उनके सामने सबसे आसान विकल्प बच्चों को काम पर भेजना बन जाता है। यही कारण है कि खेतों, कारखानों, ईंट-भट्ठों, घरेलू कामकाज और निर्माण स्थलों पर कई मासूम बच्चे काम करते नजर आते हैं। हैरत की बात है कि स्थानीय प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अक्सर आंखें मूंदे रहता है।

कोरोना महामारी के बाद यह संकट और भी गहराया है। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। दूसरी ओर, बेरोजगार हुए परिवारों में बच्चों की पढ़ाई की अपेक्षा उन्हें काम पर भेज कर पैसा कमाने को अधिक उचित समझा गया। वर्ष 2000 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में 8.55 करोड़ बच्चों की कमी दर्ज की गई थी, जो सकारात्मक संकेत था। मगर, कोरोना महामारी और आर्थिक असमानताओं ने इस प्रवृत्ति को पलट दिया और इसके बाद बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती चली गई। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी झुग्गियों तथा प्रवासी मजदूर परिवारों में यह समस्या अब अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यह स्थिति इस बात पर जोर देती है कि इस गंभीर सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए नवीन, समग्र, सामूहिक और ठोस प्रतिबद्धता की महती आवश्यकता है। बाल श्रम भारत के साथ-साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर सिर्फ बात न करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें। बाल श्रम को जड़ से उखाड़ना हमारे लिए एक चुनौती है, जिस पर खरा उतरना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है, इसके लिए सरकार को ही नहीं स्थानीय प्रशासन और परिवारों को भी आगे आना होगा। अगर समन्वित प्रयास हों, तो बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 1992 से शुरू किया गया उपक्रम बाल श्रम के क्रमिक उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय क्षमताओं को सशक्त करने और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में काम आया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का असर दिखना बाकी है। विशेष रूप से चालू वर्ष के अंत तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता कितनी सफल होगी, यह देखने की बात होगी। हालांकि, ज्यादातर अभियानों में अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली है।

> **कोरोना महामारी के बाद बाल श्रम का संकट और गहराया है। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। दूसरी ओर, बेरोजगार हुए परिवारों में बच्चों की पढ़ाई की अपेक्षा उन्हें काम पर भेज कर पैसा कमाने को ज्यादा उचित समझा गया। वर्ष 2000 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में 8.55 करोड़ बच्चों की कमी दर्ज की गई थी, जो सकारात्मक संकेत था। मगर, कोरोना और आर्थिक असमानताओं ने इस प्रवृत्ति को पलट दिया और इसके बाद बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर सिर्फ बात न करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें।**

भारत में बाल श्रम की समस्या बहुआयामी है। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा एक माध्यम हो सकती है, जो किसी भी बच्चे को श्रम के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है। सरकार का सर्वशिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जैसे प्रयास सराहनीय हैं, पर इन्हें और व्यापक बना कर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना, बाल श्रम को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' ने अब तक हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून से एक व्यापक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है। इसे राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। मगर, वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से अब तक बाल श्रमिकों का कोई भी ताजा आंकड़ा उपलब्ध न होने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग को गांव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान कर आंकड़े एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार यूनिसेफ के साथ मिल कर 'योजना पुस्तिका' तैयार कर रही है, जिसमें उन योजनाओं का विवरण होगा, जो बाल श्रमिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा मंडल स्तर पर बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रम से रोका जा सके।

बाल श्रम की इस समस्या के विरुद्ध समाज और सरकार को जनजागरण का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि यह केवल बच्चों की भलाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का सवाल है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और गरिमापूर्ण बचपन मिलना चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम निष्पक्ष, संवेदनशील और सतत रणनीतियां अपनाएं, जो ऐसे विश्व का निर्माण करें, जहां 'काम नहीं किताबें' बच्चों का अधिकार हो। तभी हम बच्चों को न केवल बाल श्रम से मुक्ति दिला सकते हैं, बल्कि देश के भविष्य की नींव भी मजबूत कर सकते हैं।

वात्सल्य के स्रोत

महेश परिमल

हमने किसी सोते हुए बच्चे को देखा होगा। उसे देखते हुए क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यह कितना मासूम है? उसके चेहरे पर जो मासूमियत होती है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वह चेहरा हमारे सामने सदैव होता है, बच्चे के बड़े होने तक। हम उसी चेहरे को हमेशा प्यार करते हैं। एक और चेहरा हमारे सामने होता है। हम कोशिश करके उसे याद कर सकते हैं। हमसे कुछ सहायता प्राप्त करने वाला या कहा जाए कि हमसे उधार मांगने वाला चेहरा। इस चेहरे के भाव कुछ अलग से होते हैं, पर वह भी मासूम ही होता है। इस चेहरे पर दो तरह के भाव पाए जाते हैं। एक तो स्वाभिमान का, दूसरा शर्म का। जो हाथ पहले कभी किसी के आगे नहीं फैले होंगे, किसी वक्त वही हाथ कुछ मांगने के लिए किसी के सामने फैलाने पड़ते हैं। जो हाथ सदैव देने के लिए उठे होते हैं, बाद में वही मांगने के लिए उठते हैं। इन दोनों भावों को हम उस वक्त देख सकते हैं, जब हमसे कोई पहली बार उधार मांग रहा हो।

मासूमियत वाले दो चेहरे और होते हैं। ये चेहरे होते हैं हमारे माता-पिता के। यह बात भले ही गले से नीचे नहीं उतर रही हो, पर यह सच है कि माता-पिता के चेहरे भी मासूम होते हैं। अगर हमें अपने माता-पिता के चेहरे पर मासूमियत नजर नहीं आ रही है, तो हमें अपनी समझदारी और दृष्टि पर गौर करने व उसमें सुधार करने की जरूरत है। अफसोस है कि हमें अपने माता-पिता कभी मासूम नहीं लगते। हालांकि, मां को इस सामाजिक व्यवस्था में मिले दर्जे की वजह से सर्वोच्च स्थान पर देखा जाता रहा है और इस नाते कई बार उनके चेहरे में मासूमियत दिखती है, जो स्वाभाविक और सही है। लेकिन पिता को आमतौर पर इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। यह वह चेहरा होता है, जो सदैव सख्त दिखाई देता है। लोग इसी सख्त और गंभीरता वाले चेहरे से डर जाते हैं। हम उनके भीतर अजस्र रूप से बहती उस स्वच्छंद नदी के प्रवाह को नहीं देख पाते, जो सदैव बना रहता है। जो देख पाते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं।

आज जीवन मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। सामाजिक जीवन अब कुछ ऐसी जटिलताओं से गुजर रहा है कि पिता-पुत्र के बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। आपाधापी इतनी है कि घर में रहने वाले और तेजी से बढ़े होते बच्चों के साथ संवाद तो जैसे गायब हो गया है। कई बार संवाद का काम आंखें ही कर लेती हैं। प्यार से गले लगाने के दृश्य तो अब यदा-कदा ही दिखाई देते हैं। पिता-पुत्र के बीच संवाद के सेतु का काम मां को ही करना होता है। जहां मां न हो, वहां तो स्थिति और भी विकट होती है। बच्चे को बड़ा होते देखना भला किसे नहीं भाता, पर बच्चा इतना भी बड़ा न बन जाए कि उससे संवाद करने के लिए वातावरण को हल्का करने की आवश्यकता पड़े। दिन भारी लगने लगते हैं, जब बच्चे से बात करने के लिए पिता को इंतजार करना पड़ता है। संभव है कई घरों में वातावरण हल्का रहता हो। पिता और पुत्र एक मित्र की तरह संवाद करते दिखाई देते हों। साथ-साथ घूमने जाना, एक साथ मिल कर भोजन करना आदि क्रियाकलाप हों। ऐसे माहौल में पता ही नहीं चलता कि घर में किसकी चलती है, पिता की या बेटे की। एक उम्र के बाद पिता और भी अधिक खामोश होने लगते हैं। कई चीजें उनकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, वे आंखें उसे स्वीकार नहीं करतीं, पर पिता के सामने उसे स्वीकारने की विवशता भी होती है। एक अनजाना-सा संवाद उनके भीतर ही उमड़ता-घुमड़ता रहता है, जिसे वे शब्द देना चाहते हैं। मगर, वे शब्द होठों तक आते-आते रह जाते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **आज जीवन मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। सामाजिक जीवन अब कुछ ऐसी जटिलताओं से गुजर रहा है कि पिता-पुत्र के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। आपाधापी इतनी है कि घर में रहने वाले और तेजी से बढ़े होते बच्चों के साथ संवाद तो जैसे गायब हो गया है। कई बार संवाद का काम आंखें ही कर लेती हैं।**

जिसने भी माता-पिता की मासूमियत को पहचान लिया, वह उतना ही अधिक भाग्यशाली होता है। माता-पिता कभी भी अपने बच्चों को यह नहीं बताते कि उन्होंने उसके लिए क्या-क्या किया। इसे बच्चा ही अगर ठीक से समझे, तो बेहतर होता है। जो संतान अपने माता-पिता की मासूमियत को जानती है, वह अपने जीवन में कभी विफल नहीं हो सकती। उसके जीवन की चुनौतियों के आगे उसके माता-पिता का संघर्ष, समर्पण और त्याग होता है। धीरे-धीरे बड़ा होता बच्चा उनके इस संघर्ष का मौन साक्षी होता है। बच्चे का यही मौन तब मुखर होता है, जब वह मां या पिता बनता है। इसके लिए उसे समय की बहुत ही लंबी नदी को तैरकर पार करना होता है।

माता-पिता खामोश कविता की तरह होते हैं। उनकी खामोशी के पीछे ही छिपा होता है प्यार का अजस्र स्रोत, जो सदैव प्रवाहमान होता है। इसमें भीगने का अवसर बहुत ही कम संतानों को मिलता है। पर जिसे भी मिलता है, वह निहाल हो उठता है। चट्टान के नीचे मीठे पानी का सोता ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में यह परिश्रम होता है, जो अनजाने में उनसे ही संतानों को विरासत के रूप में मिलता है। खामोश कविता सदैव हमारे जीवन में अपना असर दिखाती रहे तो जीने की राह और आसान हो जाती है।

लोकतंत्र का तकाजा

पश्चिम में आज भी कई देश ऐसे हैं, जिनके लोकतंत्र पर पूरी दुनिया को गर्व होना चाहिए। इन देशों में आज भी सरकारों के निर्वाचित होने के बाद नीति में बदलाव या नई नीति लागू करने के वक्त जनमत संग्रह करवाया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जनता ने तो उन्हें एक बार मतदान देकर सिर्फ चुना था, पर उसे चुन लेने का मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नया कानून या बदलाव लागू कर दे। इसके लिए पश्चिमी देशों की कुछ सरकारें वापस जनता के पास जाकर उनका मत जानना चाहती हैं कि नया बदलाव हमें करना चाहिए या नहीं। चौते रविवार को इटली में रायशुमारी का पहला दौर था। जिसमें लोगों को आप्रवासन को लेकर कुछ बदलावों पर अपनी राय देनी है। लाखों आप्रवासियों का भाग्य दांव पर है। जनमत संग्रह में बेहतर नौकरी व सुरक्षा के लिए श्रम सुधारों को भी वापस लेने की मांग की गई है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

सेहत की फिक्र

आज के दौर में कुछ लोगों को ही सही मायने में सेहत की फिक्र होती है। इसी का नतीजा है कि देश में पारंपरिक और प्राकृतिक खेती पर जोर नहीं दिया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि खेती में बढ़ते कीटनाशकों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। एक समय में जो भूमि किसानों के लिए उपजाऊ हुआ करती थी, आज वहां उपज कम हो रही है। रासायनिक खाद ने समस्या बढ़ाई है। अधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से उपजाए गए अन्न को स्वास्थ्यवर्धक नहीं कहा जा सकता। अगर, इन समस्याओं से बचना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की दोबारा अपनाना होगा। बाजार में भी प्राकृतिक उत्पादों की मांग है। वैसे अब राज्य सरकारें इस ओर प्रयास कर रही हैं। प्राकृतिक खेती हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है और यह समय की मांग बन चुकी है।

– साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

संवेदनशीलता का लोप

रायल चैलेंजर्स बैंगलुरु की जीत का जश्न उस क्षण भयावह दुस्स्वप्न बन गया, जब प्रशासन की लापरवाही के कारण मची भगदड़ ने स्यारह जिंदगियां लील लीं। दरअसल, सुरक्षा प्रबंधन के नाम पर योजनाएं केवल कागज पर थीं, मार्गदर्शन केवल नारों में सीमित था और बाद में सरकारी घोषणाओं में सहायता राशि का ही जिक्र था। जिन सड़कों पर जयकारे गूंजने थे, वहां चीखें सुनाई दीं। जिन चेहरों पर रंग होना था, वहां खून था। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, परंतु उन लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा, जिनके अपने असमय काल के गाल में समा गए। भारत उत्सवों की भूमि है। मगर, ऐसे आयोजनों में संवेदनशीलता के साथ जन-सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। जिसमें प्रशिक्षित स्वयंसेवक हों, मार्गदर्शक संकेत हों, निकासी के उपाय हों और प्रबंधन चाक-चौबंद हो।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

दोहरा चरित्र

जहां एक तरफ भारत आर्थिक व सैन्य ताकत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं हमारे पड़ोसी देशों की ईर्ष्या कम नहीं हो रही। चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान। पिछले दिनों आपरेशन सिंदूर से पाक को मुंह की खानी पड़ी। मगर, पश्चिमी मीडिया का कथन कुछ और ही है। वे अलग आख्यान रच रहे थे, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद पश्चिमी मीडिया को आतंकवाद नजर आ रहा था। मगर, पाकिस्तान में घुस कर 9/11 के सात्रिशकर्ता लादेन को मारने वाले लोग ही आज उसके के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जबकि वह अपने यहां आतंकवाद को संरक्षण देता है। यह पश्चिमी मीडिया का दोहरा चरित्र है, जो भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है।

– सचिन पांडेय, इलाहाबाद